संकट में नेबरहुड फर्स्ट नीति

दुनिया

भारत की विदेश नीति हमेशा से ही मालदीव के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की रही है। लेकिन नए राष्ट्रपति दशकों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ भारत के बजाय चीन को तवज्जो दे रहे हैं

पृष्ठ 12

नहीं रहे सांझी विरासत के पैरोकार

स्मृति-शेष

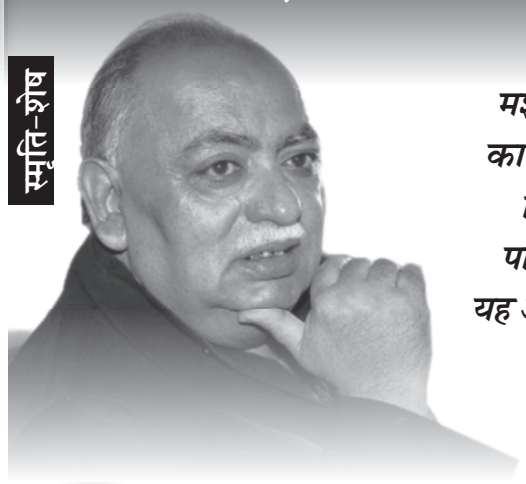

मशहूर शायर मुनव्वर राना का जाना जैसे मछलियों के लिए एकाएक समुंदर से पानी सूख जाने समान है। यह अदब और अवाम, दोनों के हिस्से का साझा नुकसान है

पृष्ठ 14

दि संडे पोस्ट

2001 से प्रकाशित

21 जनवरी से 27 जनवरी 2024, मूल्य : 3:00

हर रविवार को देहरादून से प्रकाशित

ना काहू से दोस्ती - ना काहू से बैर

वर्ष 15, अंक : 32, उत्तराखण्ड संस्करण (पृष्ठ 16)

वेबसाइट www.thesundaypost.in

सुप्रीम कोर्ट ने नदियों को जीवित प्राणी की संज्ञा दी है। जीवनदायनी नदियों के अस्तिव को बचाने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। नदियों के किनारे हो रहे निर्माण कार्यों के लिए तय मानकों अनुसार किसी भी प्रकार का मलबा नदियों में नहीं डाला जा सकता है। इसके लिए डंपिंग जोन बनाए जाने की व्यवस्था है। लेकिन उत्तराखण्ड का लोक निर्माण विभाग अपनी सुविधा के लिए चोरी-छिपे मलबे को नदियों में डालकर उनके प्रवाह में बाधक बन रहा है। अति तो तब हो जाती है जब अधिकारी विकास के रास्ते में मलबे को जायज ठहराते हैं। गंगा की सहायक नदी नयार पर प्रहार की यह गाथा उत्तराखण्ड की हकीकत को बयां करती है

नयार पर प्रहार

आवरण-कथा

पृष्ठ 5

आंचल पर आंच

खास-खबर

दुग्ध एवं डेयरी विभाग के घपले-घोटालों की हकीकत सामने आई है। खुद शासन ने भ्रष्टाचार में आरोपित अधिकारियों पर कार्रवाई कर इसकी पुष्टि कर दी है। यह कार्रवाई मेलामाइन की दूध में मिलावट को लेकर की गई है। इससे आंचल पर आंच आने लगी है। मेलामाइन एक घातक पदार्थ है जिसके मानकों से अधिक पाए जाने पर कैंसर जैसी घातक बीमारी पनपने लगती है

पृष्ठ 7, 8

ईसाई समुदाय को लुभाने में जुटे मोदी

राम पुनियानी
लेखक राष्ट्रीय एकता मंच के संयोजक हैं।

अगला आम चुनाव नजदीक है और आरएसएस-भाजपा ने ईसाई समुदाय को लुभाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जहां तक ईसाई समुदाय की वर्तमान स्थिति का सवाल है, उसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रपटों और धार्मिक स्वतंत्रता सूचकांकों से समझा जा सकता है। 'वादा न तोड़ो अभियान' के अनुसार देश में हर दिन ईसाइयों की प्रताड़ना की दो घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में ... 'करीब 100 पास्टर और आम पुरुष और महिलाएं भी गैर-कानूनी धर्मपरिवर्तन करवाने के आरोप में जेलों में बंद हैं, जबकि वे या तो जन्मदिन मना रहे थे या इतवार की विशेष प्रार्थना सभा कर रहे थे।' इस समय प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं, वह केवल छवि बनाने की कवायद है। केरल में कई धनी ईसाई इस हिंदू बहुसंख्यकवादी राजनीति के जाल में फंस रहे हैं। यह भी सच है कि ईडी, इनकम टैक्स आदि के कहर से बचने के लिए ईसाई समुदाय के शीर्ष धार्मिक नेतृत्व का एक हिस्सा सरकार के साथ खड़ा होने को आतुर है

गत २५ दिसंबर, २०२३ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ईसाइयों को क्रिसमस की बधाई देने और उनसे बातचीत करने के लिए अपने घर निमंत्रित किया। उन्होंने समाजसेवा के क्षेत्र में ईसाई समुदाय के योगदान और प्रभु ईसा मसीह की समावेशी शिक्षाओं की सराहना की। उन्होंने ईसाई समुदाय के नेताओं से अपने पुराने और लम्बे संबंधों के बारे में भी अपने मेहमानों को बताया। इसके कुछ दिन बाद केरल में सैकड़ों ईसाइयों ने भाजपा की सदस्यता ले ली। 'द हिंदू' ने लिखा : 'भाजपा की राज्य इकाई की कोट्टयम में हुई बैठक में तय किया गया कि ईसाई समुदाय को आकर्षित करने के लिए १० दिन की स्नेह यात्रा निकाली जाएगी जिसके दौरान पार्टी मणिपुर हिंसा सहित विभिन्न मसलों पर अपनी बात समुदाय के सामने रखेगी।' केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बिलकुल ठीक कहा कि 'मणिपुर में हालत यह हो गई है कि ईसाई समुदाय का एक हिस्सा वहां रह ही नहीं सकता। हम सबने देखा है कि इस मामले में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने चुप्पी साध रखी है।'

(द इंडियन एक्सप्रेस, मुंबई, जनवरी २ २०२४)

अगला आम चुनाव नजदीक है और आरएसएस-भाजपा ने ईसाई समुदाय को लुभाने के प्रयास शुरू कर दिए है। जहां तक ईसाई समुदाय की वर्तमान स्थिति का सवाल है, उसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रपटों और धार्मिक स्वतंत्रता सूचकांकों से समझा जा सकता है। 'वादा न तोड़ो अभियान' के अनुसार देश में हर दिन ईसाइयों की प्रताड़ना की दो घटनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में... 'करीब १०० पास्टर और आम पुरुष और महिलाएं भी गैर-कानूनी धर्मपरिवर्तन करवाने के आरोप में जेलों में बंद हैं, जबकि वे या तो जन्मदिन मना रहे थे या इतवार की विशेष प्रार्थना सभा कर रहे थे।'

एक ज्ञापन के अनुसार सरकार कार्डिनलों और पास्टरों के खिलाफ अपनी विभिन्न जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भी कर रही है। यूनाइटेड क्रिस्चियन फोरम के अनुसार, सन २०२२ के पहले सात महीनों में ईसाइयों पर हमलों की ३०२ घटनाएं हुईं। नेशनल सॉलिडेरिटी फोरम एंड इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के आर्चबिशप पीटर मेकेडो द्वारा दायर एक याचिका के मुताबिक 'राज्य ऐसे समूहों के खिलाफ त्वरित और आवश्यक कार्यवाही करने में असफल रहा है जिन्होंने ईसाई समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा की, नफरत फैलाने वाले भाषण दिए, उनके आराधना स्थलों पर हमले किए और उनकी प्रार्थना सभाओं में व्यवधान उत्पन्न किए।'

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने लगातार चौथे साल भारत को 'विशेष सरोकार' वाला देश निरुपित किया है और अमेरिकी सरकार से कहा है कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाए। ओपन डोर्स के अनुसार, 'वर्तमान सरकार के मई २०१४ में सत्ता में आने के बाद से ईसाइयों पर दबाव में नाटकीय वृद्धि हुई है। हिंदू अतिवादी अन्य धर्मों के लोगों पर बिना किसी भय के हमले करते हैं और कुछ इलाकों में उन्होंने गंभीर हिंसा की है। बड़ी संख्या में राज्य सरकारें धर्मांतरण-विरोधी कानून लागू कर रही हैं जिनका घोषित उद्देश्य हिंदुओं का जबरदस्ती दूसरे धर्मों में परिवर्तन रोकना है मगर असल में उनके बहाने ईसाइयों को धमकाया और प्रताड़ित किया जाता है। पास्टर होना इस देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाला काम बन गया है। हिंदू अतिवादी पास्टरों पर हिंसक हमले करते हैं ताकि आम ईसाइयों के मन में डर का भाव बैठाया जा सके।'

ईसाई समुदाय की वर्तमान स्थिति की जड़ में है हिंदू राष्ट्रवादी आख्यान जिसमें इस्लाम और ईसाईयत को विदेशी धर्म माना जाता है। आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'बंच ऑफ थॉट्स' में लिखा है कि ईसाई और कम्युनिस्ट, हिंदू राष्ट्र के आर्तरिक शत्रु हैं।

आरएसएस की शाखाओं में भी इसी आशय की बातें सिखाई जातीं हैं। हिंदू राष्ट्रवादी गतिविधियों में उछाल के साथ ईसाइयों के खिलाफ हिंसा सबसे पहले देश के आदिवासी इलाकों में शुरू हुई प्रचार यह किया गया कि ईसाई मिशनरीज जबरिया, धोखाधड़ी और लोभ-लालच से आदिवासियों को ईसाई बना रही हैं। ईसाई धर्म भारत के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि सेंट थॉमस मालाबार के तट पर उतरे और ५२ ईस्वीं में उन्होंने वहां देश के पहले चर्च की स्थापना की। कुछ अन्य स्त्रोतों के अनुसार वे चौथी सदी में मालाबार आए थे। सन २०११ की जनगणना के अनुसार, देश की कुल आबादी में ईसाइयों का प्रतिशत २३ है। मजे की बात यह है कि सन १९७१ से इसमें लगातार गिरावट आ रही है : १९७१- २६० प्रतिशत, १९८१-२४४ प्रतिशत, १९९१-२३४ प्रतिशत, २००१-२३० प्रतिशत, २०११-२३० प्रतिशत (सभी आकंड़े जनगणना से)।

मगर बेसिर पैर के दुष्प्रचार के नतीजे में गुजरात के डांग में सबसे पहले (२५ दिसंबर १९९८ से लेकर ३ जनवरी १९९९ तक) ईसाई-विरोधी हिंसा हुई इसकी बाद, २२ जनवरी १९९९ की रात आरएसएस के अनुषांगिक संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता राजेंद्र पाल उर्फ दारासिंह ने पास्टर ग्राहम स्टेंस और उनके दो मासूम पुत्रों को जिंदा जला दिया। दारा सिंह इस समय उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस घटना को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ केआर नारायणन ने 'दुनिया के काले कारनामों की सूची का हिस्सा। बताया। स्टेंस ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी थे और उड़ीशा के क्योंझर, मनोहरपुर में काम करते थे। जब वे अपने दो बच्चों टिमोथी और फिलिप के साथ एक खुली जीप में सो रहे थे तब दारासिंह ने कुछ लोगों के साथ मिलकर तीनों को जिंदा जला दिया। आरोप यह लगाया कि कुष्ठ रोगियों की सेवा के बहाने वे धर्मपरिवर्तन करवा रहे थे।

घटना की जांच के लिए नियुक्त वाधवा आयोग ने पाया कि पास्टर स्टेंस धर्मपरिवर्तन में संलग्न नहीं थे और जिस इलाके में वे काम कर रहे थे वह की ईसाई आबादी में कोई बढोतरी नहीं हुई थी। इसके बाद से दूर-दराज के इलाकों में ईसाई-विरोधी हिंसा जारी रही। अधिकांश मामलों में इस तरह की हिंसा क्रिसमस के आसपास होती थी। फिर २५ अगस्त २००८ को उड़ीशा के कंधमाल में भयावह हिंसा शुरू हुई जिसमें १०० से ज्यादा ईसाई मारे गए, ईसाई महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली बलात्कार की घटनाएं हुईं और कई चर्चों को आग के हवाले कर दिया गया। तब से ईसाई-विरोधी हिंसा चल ही रही है यद्यपि यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस पर ज्यादा शोर शराबा न हो। अक्सर दूर-दराज के इलाकों में काम कर रहे पादरियों को तब घेरा जाता है जब वे प्रेयर मीटिंग संचालित कर रहे हों। बजरंग दल और उसके जैसे अन्य संगठनों के सदस्य प्रेयर मीटिंग्स में बांधा डालते हैं। पादरियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है।

मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ करीब सात महीनों से हिंसा चल रही थी। कुकी, जिनमें से अधिकांश ईसाई हैं, डबल इंजन सरकार के निशाने पर हैं। मणिपुर और दिल्ली दोनों में भाजपा की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस ईसाई-विरोधी हिंसा को रोकना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। वे दुनिया भर में जा रहे हैं मगर मणिपुर के लिए उनके पास वक्त नहीं है। कुछ हिम्मतवर सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इस इलाके में भ्रमण कर हिंसा की आग को बुझाने का प्रयास किया लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते इस खाई को भरना मुश्किल होगा। इस समय प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं, वह केवल छवि बनाने की कवायद है। केरल में कई धनी ईसाई इस हिंदू बहुसंख्यकवादी राजनीति के जाल में फंस रहे हैं। यह भी सच है कि ईडी, इनकम टैक्स आदि के कहर से बचने के लिए ईसाई समुदाय के शीर्ष धार्मिक नेतृत्व का एक हिस्सा सरकार के साथ खड़ा होने को आतुर है।

हमें यह समझना होगा कि मोदी एंड कंपनी एक तरफ तो ईसाई समुदाय को हाशिए पर धकेल देना चाहते हैं तो दूसरी ओर वे चुनावों में उनके वोट भी हासिल करना चाहते हैं।

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनियाय लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन २००७ के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)

21 जनवरी से 27 जनवरी 2024 तक के लिए प्रकाशित

संपादक : अपूर्व* कार्यकारी संपादक (विचार) : आदेश भाटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी : सुनील भारद्वाज, रोविंग एसोसिएट एडिटर : आकाश नागर
उप संपादक : जीवन सिंह टनवाल, जनार्दन कुमार सिंह, मो. रुस्तम, नीतू टीटाण उत्तराखण्ड प्रभारी : दिव्य सिंह रावत, विशेष संवाददाता : कृष्ण कुमार, मुख्य संवाददाता
कुमाऊं : संजय स्वार, संवाददाता : दिनेश पंत, गोपाल बोरा, गढ़वाल संवाददाता : जसपाल नेगी, अली खान, प्रबंधक : अमित कुमार : 9582371321 **प्रधान कार्यालय :** बी-107, सेक्टर-63, नोएडा, फोन : 0120-4330755, फैक्स : 0120-4352397,
उत्तराखण्ड कार्यालय : रोहणी प्लाजा, कॉम्प्लेक्स, 28 दूसरी मंजिल 11 ई, राजपुर रोड, देहरादून, मो. : 09412901406 **कुमाऊं कार्यालय :** प्रथम तल, नंदा इंक्लेव, नरसिंह तल्ला, कमलवागांजा रोड हल्द्वानी-263139, नैनीताल।
* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी। स्वत्वाधिकारी इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसायटी के लिए प्रकाशक, मुद्रक नारायण सिंह राणा द्वारा बी.एफ.एल. इन्फोटेक लि., सी-9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित एवं 3, रोहणी प्लाजा, कॉम्प्लेक्स, 28 दूसरी मंजिल 11 ई, राजपुर रोड, देहरादून से प्रकाशित।

मानवाधिकारों का गहराता संकट

अपूर्व
editor@thesundaypost.in

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताजातरीन रिपोर्ट में मणिपुर में गत् वर्ष मैती-कुकी हिंसा से लेकर भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ महिला पहलवानों का आंदोलन तथा जम्मू-कश्मीर के ताजा हालातों का जिक्र करते हुए कहा है कि मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले लोकतांत्रिक देश के बतौर भारत का प्रदर्शन खासा निराशाजनक रहा है। बीते कई वर्षों से भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना का शिकार होते रहे हैं। गत् वर्ष उनकी पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान भी यह मुद्दा वहां की संसद के कुछ सदस्यों ने उठाने का प्रयास किया था। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी सिनेट के 70 सदस्यों ने राष्ट्रपति जो बाइडन को एक पत्र लिखकर मांग की थी कि राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत में भारत में मानवाधिकारों के संकट का मुद्दा अवश्य उठाएं। हालांकि भारत सरकार इस प्रकार के आरोपों को सिरे से नकारती आई है और विभिन्न वैश्विक मंचों पर उसके द्वारा इस प्रकार के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया जाता रहा है लेकिन ऐसे समय में जब भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बन उभर चुका है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का अपना सपना साकार करने के लिए सतत् प्रयत्नशील हों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारतीय लोकतंत्र पर अविश्वास व्यक्त करना और भारत में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन् की बात करना निःसंदेह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र बतौर हमारी प्रतिष्ठा और लोकतंत्र के स्वास्थ पर प्रतिकूल असर डालता है

वर्ष १९७८ में अमेरिका के तीन नागरिकों ने एक गैर-सरकारी संगठन 'हेलसिंकी वॉच' का गठन विश्वभर में मानवाधिकारों की स्थिति सामने लाने के उद्देश्य से किया था। आज यह संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (#Human rights watch) के नाम से जाना जाता है। इस संगठन को उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए १९९७ में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। यह संगठन मुख्य रूप से विश्व भर में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन, विशेषकर सरकारों द्वारा राज्य सत्ता का दुरुपयोग कर अपने नागरिकों के अधिकारों में कटौती करने, लिंग भेद के प्रकरणों की छानबीन करने, युद्ध में नाबालिगों को इस्तेमाल करने तथा वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अपनी तथ्यपरक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी करता है। इस संगठन का जिक्र इसलिए क्योंकि इसने ११ जनवरी को जारी अपनी 'वर्ल्ड रिपोर्ट २०२४' में भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर खासी नकारात्मक बातें कही हैं। भारतीय विपक्षी राजनीतिक दल और मानवाधिकार कार्यकर्ता काफी अर्से से वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान पर इस प्रकार के आरोप लगाते आ रहे हैं। अब एक ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय संगठन का इन आरोपों की पुष्टि करना वैश्विक स्तर पर भारत की साख को प्रभावित तो करता ही है, मोदी सरकार का नारा 'सबका साथ-सबका विश्वास' की विश्वसनियता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताजातरीन रिपोर्ट में मणिपुर में गत् वर्ष मैती-कुकी हिंसा से लेकर भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का आंदोलन तथा जम्मू-कश्मीर के ताजा हालातों का जिक्र करते हुए कहा है कि मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले लोकतांत्रिक देश के बतौर भारत का प्रदर्शन खासा निराशाजनक रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गत् वर्ष मानवाधिकारों के दमन और उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाओं की बाबत इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है। विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सरकार के आलोचकों की गिरफ्तारी और कई मामलों में आतंक निरोधी कानूनों का इस्तेमाल, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। इस संगठन की एक वरिष्ठ अधिकारी मीनाक्षी गांगुली के अनुसार 'भाजपा सरकार की भेदभाव पूर्ण और विभाजनकारी नीतियों के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है, इससे डर का माहौल बना है और सरकार की आलोचना करने वालों में भय पैदा हुआ है।'

रिपोर्ट में बीबीसी के दफ्तरों में गत् वर्ष फरवरी में आयकर विभाग की छापेमारी का जिक्र करते हुए इसे प्रतिशोध की कार्यवाही बताया गया है। स्मरण रहे कि गत् वर्ष बीबीसी न्यूज चैनल द्वारा दो भागों में एक डाक्यूमेंट्री फिल्म- 'इंडियाः द मोदी क्वेश्चन' का प्रसारण किया गया था। यह फिल्म भारत में खासी विवादित रही थी। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को मुस्लिम विरोधी बताया गया था। केंद्र सरकार ने आईटी कानून के अंतर्गत इस फिल्म को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। बीबीसी के भारत स्थित दफ्तरों में इस फिल्म के प्रसारण बाद ही छापे पड़े थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में इसे बदले की कार्यवाही कहा है।

गत् वर्ष जुलाई में हरियाणा के नूंह शहर में हुई हिंसा का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने इस हिंसा के लिए मुसलमानों को दोषी मानते हुए एकतरफा कार्यवाही की थी। मणिपुर में मैतई और कुकी समुदायों के बीच कई महीनों तक चली हिंसा की बाबत भी इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है। रिपोर्ट में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह की कार्यशैली पर कठोर टिप्पणी की गई है। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए वहां हुई हिंसा में महिलाओं और लड़कियों संग यौन हिंसा का विशेष रूप से जिक्र किया था। जम्मू-कश्मीर के हालातों पर भी इस रिपोर्ट में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। बकौल ह्यूमन राइट्स वॉच वहां अभिव्यक्ति की आजादी और आम जनता द्वारा विरोध-प्रदर्शनों पर पाबंदी गंभीर मानवाधिकारों की श्रेणी में आता है। दिसंबर माह में सैन्य बलों द्वारा आतंकी हमले के बाद ९ सिविलियों को पूछताछ के लिए ले जाने और उनमें से तीन की सैन्य हिरासत के दौरान कथित उत्पीड़न चलते मौत की बाबत भी इस रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर नामी-गिरामी महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का उल्लेख भी इस रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने बृजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश की और महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने न केवल दुव्यवहार किया बल्कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी जबरन खत्म कराया।

यह रिपोर्ट भारत में आम चुनाव से ठीक पहले जारी की गई है। बीते कई वर्षों से भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचना का शिकार होते रहे हैं। गत् वर्ष उनकी पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान भी यह मुद्दा वहां की संसद के कुछ सदस्यों ने उठाने का प्रयास किया था। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी सिनेट के ७० सदस्यों ने राष्ट्रपति जो बाइडन को एक पत्र लिखकर मांग की थी कि राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत में भारत में मानवाधिकारों के संकट का मुद्दा अवश्य उठाएं। इस पत्र की भाषा बेहद कठोर थी। इसमें कहा गया था- A series of independent, credible reports reflect troubling signs in India towards the shrinking of political space, the rise of religious intolerence, the targeting of civil society organizations and journalists and growing restrictions on press freedom and internet access.' प्रधानमंत्री मोदी की कटु आलोचकों में शुमार अमेरिकी सांसद रशीदा तैयब ने मोदी की इस यात्रा का बहिष्कार यह कहते हुए तब किया था कि 'भारतीय प्रधानमंत्री का अतीत मानवाधिकरों के हन्न, लोकतंत्र विरोधी कार्यवाही, मुसलमानों को निशाने पर रखने और पत्रकारों के उत्पीड़न से भरा हुआ है इसलिए मैं अमेरिकी संसद में उनके संबोधन का बहिष्कार करूंगी।'

हालांकि भारत सरकार इस प्रकार के आरोपों को सिरे से नकारती आई है और विभिन्न वैश्विक मंचों पर उसके द्वारा इस प्रकार के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया जाता रहा है लेकिन ऐसे समय में जब भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत बन उभर चुका है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने का अपना सपना साकार करने के लिए सतत् प्रयत्नशील हों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारतीय लोकतंत्र पर अविश्वास व्यक्त करना और भारत में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के हनन् की बात करना निःसंदेह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र बतौर हमारी प्रतिष्ठा और लोकतंत्र के स्वास्थ पर प्रतिकूल असर डालता है। यहां यह भी विचारणीय है कि आपातकाल के बाद पहली बार इस प्रकार की बातें तेजी से उठने लगी हैं। मोदी के आलोचक वर्तमान समय को आपातकाल से कहीं ज्यादा घातक करार दे रहे हैं। समाज के एक बड़े तबके का मानना है कि बीते कुछ वर्षों से हम अघोषित आपातकाल के माहौल में जी रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती और शक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का होना है। हमारे मुल्क का हश्र पाकिस्तान सरीखा न होने के पीछे लोकतंत्र की इस शक्ति का होना ही तो है। सत्ता यदि अपनी आलोचना के डर से इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन पर उतारू होती है तो इसके नतीजे भयावह हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी प्रति आम जनता का विश्वास लेकिन तभी बना रह सकता है जब वे जनता जनार्दन के मन की बात को खुले हृदय से सुने, फिर चाहे वह उनके खिलाफ उठ रहे स्वर ही क्यों न हों। हम विश्वगुरु बन सकते हैं लेकिन यह तभी संभव है जब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी निष्ठा अक्षुण रहे। हमें याद रखना होगा कि हमारी ताकत हमारे लोकतंत्रिक मूल्य और आदर्श हैं। इनके प्रति यदि हमारी निष्ठा कमजोर हुई तो यह हमारे लिए बेहद आत्मघाती होगा।

सरगोशियां

'आप' ने मानी कांग्रेस की बात!

लोकसभा चुनाव २०२४ में भाजपा और पीएम मोदी को पटखनी देने के लिए बने इंडिया गठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली की लोकसभा सीटों पर बात लगभग बन गई है। माना जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ४-३ के फॉर्मूले पर सहमति बनी है और पंजाब में भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। इससे पहले २०१९ लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कोशिश हुई थी लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई थी। राजनीतिक पंडितो का कहना है कि २०२४ आम चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया बना तो है लेकिन अभी ज्यादातर प्रदेशों में सीट शेयरिंग का मसला सुलझता नहीं दिख रहा है। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ही दिल्ली की सातों सीटें जीती हैं। गठबंधन के लिए दोनों दलों की उत्सुकता इसलिए भी है कि उन्हें उम्मीद है कि इससे दिल्ली में बीजेपी को हराना आसान हो सकेगा। गौरतलब है कि यह बैठक कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हुई जिसमें दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने चर्चा की। गठबंधन को लेकर एक ही मसला अहम है कि कांग्रेस और आप दोनों ही दिल्ली में ४ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस से नाराज होने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में हुई यह बैठक कांग्रेस को एक मोर्चे पर राहत दे सकती है क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के साथ सहमति बन जाती है तो दिल्ली और पंजाब दोनों जगह गठबंधन हो पाएगा।

एकला चलो की राह पर बसपा

आगामी आम चुनाव की तैयारियों में जुटे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सुर इन दिनों बदले-बदले से नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हुई एक बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं को नसीहत दी कि बहुजन समाज पार्टी पर विवादित बयानबाजी करने से बचें और उनका सम्मान करें। उनके इस अंदाज के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने बसपा के इंडिया अलायंस में शामिल होने पर अपना रुख बदल लिया है और बसपा की इंडिया में एंट्री पर लगाई अपनी नामंजूरी को हटा दिया है। ऐसे में सवाल रहे थे कि क्या अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। इस बात को बल हाल में दिए गए बसपा सुप्रीमो के बयानों से मिल भी रहा था। बसपा प्रमुख मायावती ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके बारे में किसी का भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरी उन्हें सलाह है कि वह इससे बचें, क्योंकि भविष्य में कब किसको, किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मायावती के इस बयान के बाद माना जा रहा था कि उनका यह बयान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को केंद्रित करके दिया गया है। लेकिन १५ जनवरी यानी अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने बड़ा एलान कर इंडिया और एनडीए दोनों अलायंस में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा आम अकेले चुनाव लड़ेगी। अलायंस में वोट ट्रांसफर नहीं होता। हमारी पार्टी चुनाव अकेले इसलिए लड़ती है क्योंकि इसकी कमान एक दलित के हाथों में है। हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। साल २००७ की तरह हमारी पार्टी इस चुनाव में भी बेहतर परिणाम देगी। गठबंधन करने पर हमारा वोट तो उन्हें मिल जाता है मगर उनका वोट खासकर सवर्ण वोट हमें नहीं मिलता है। गठबंधन में चुनाव लड़ने से बसपा को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है।

साइकिल पर सवार हो सकते हैं अफजल

आगामी आम चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की नजर उन उम्मीदवारों पर है जो चुनाव में पार्टी को जीत दिला सकें। इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद गाजीपुर सीट को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी ने यहां अपना उम्मीदवार लगभग तय कर लिया है। कहा जा रहा है कि सपा अफजल अंसारी को गाजीपुर से चुनाव मैदान में उतार सकती है। अफजल सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात के कयास हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अंसारी की बेटी की शादी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के शामिल होने बाद से लगाए जा रहे हैं। इस दौरान अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल यादव, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, विधायक वीरेंद्र यादव, विधायक जयकिशन साहू और जिला अध्यक्ष गोपाल यादव भी मौजूद थे। जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अंसारी की बेटी की शादी लखनऊ में हुई थी। इस समारोह में समाजवादी कुनबे के बड़े नेताओं के साथ अखिलेश यादव जिस तरह इस शादी में शामिल हुए उससे इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि सपा अफजल अंसारी को गाजीपुर से आम चुनाव के मैदान में उतार सकती है। चर्चा है कि अफजाल का झुकाव भी इन दिनों सपा की ओर दिखाई दे रहा है। चर्चा यह भी गरम है कि सपा नेतृत्व कई अन्य दिग्गज बसपा नेताओं के संपर्क में है और उन्हें सपा से चुनाव लड़ाने का प्रयास कर रहा है।

कांग्रेस ने क्यों ठुकराया आमंत्रण?

फोटो : टीवी 9 पोर्टल से

दि संडे पोस्ट डेस्क

आगामी आम चुनाव २०२४ में अब कुछ ही महीने शेष हैं। इसके मध्य नजर सभी राजनीतिक पार्टियां तेजी से सक्रिय होने लगे हैं। देश की सत्तारूढ़ दल भाजपा एक ओर जहां एक फिर राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिशों में रातदिन जुटी है वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने करीब तीन सप्ताह तक सियासी नफा-नुकसान का आकलन करने के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक करार देकर निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो पार्टी राम मंदिर के ताले खुलवाने का श्रेय लेती है आखिर उसने क्यों ठुकराया आमंत्रण?

क्या कांग्रेस ने इस निर्णय से साफ कर दिया है कि राजनीतिक लाभ-हानि के मुकाबले उसके लिए विचारधारा ज्यादा अहम है? क्या इस निर्णय से पार्टी ने अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को धार देने की कोशिश की है? पार्टी सूत्रों की मानें तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के भीतर काफी विचार-विमर्श हुआ। इस मुद्दे पर पार्टी में दो राय थी। एक तबका चाहता था कि पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर कोई नेता कार्यक्रम में शामिल हों, जबकि दूसरा पक्ष चाहता था कि यह राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए पार्टी को इससे दूर रहना चाहिए। आखिरकार पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस निमंत्रण स्वीकार कर भाजपा के एजेंडे में नहीं फंसना चाहती थी, क्योंकि कार्यक्रम में शामिल होने के बावजूद भाजपा से सीधा मुकाबले वाले राज्यों में उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता।

दूसरा कांग्रेस को डर था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से दक्षिण भारत में गलत संदेश जा सकता है। दक्षिण के नेता पहले ही पार्टी पर कार्यक्रम में न जाने का दबाव बना रहे थे। कर्नाटक और तेलंगाना में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पिछले चुनाव में पार्टी को दक्षिण से २८ सीट मिली थी। केरल में पार्टी ने २० में १५ सीट पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में पार्टी ने दक्षिण को ध्यान में रखते हुए निमंत्रण में नहीं जाने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ एकजुटता दिखाने का भी प्रयास किया है। क्योंकि गठबंधन के कई दलों के नेताओं को न्योता नहीं मिला है। कई दल अयोध्या जाने से इनकार कर चुके हैं।

इन पार्टियों का कहना है कि वे प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक कार्यक्रम मानती हैं, यही वजह है कि रणनीतिकार काफी सोच-विचार के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि भाजपा के एजेंडे में फंसने के बजाय विचारधारा को मजबूती देना ज्यादा अहम और आने वाले समय में फायदेमंद साबित होगा। दूसरा कारण यह कि कांग्रेस ने इसके जरिए भाजपा की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से खुद को अलग रखने का भी संकेत दिया है।

गौरतलब है कि हाल ही में हुए हिंदी पट्टी के तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश की थी। यहां तक कि कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा भी कराई थी लेकिन विधानसभा में मतदाताओं ने कांग्रेस की इस कोशिश को ठुकरा दिया। इसलिए धर्म को व्यक्तिगत विषय बताते हुए पार्टी ने राजनीतिक दल के तौर पर खुद को अलग कर लिया है।

बिहार में हो सकता है बड़ा खेला

इन दिनों देश की राजनीति एक ओर जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर केंद्रित है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में सियासी सरगर्मियां सुलगने लगी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि मकर संक्रांति के बाद राज्य में बड़ा खेला हो सकता है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी २७ जनवरी को बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। ऐसे में इस बीच बिहार में बड़ा खेल होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों एक बयान में कहा था कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उनके इस बयान को अब जेडीयू नेताओं के बयान से बल मिलने लगा है। पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी पार्टी बिहार की जीती हुई सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर जिसे समझौता करना है करें। गौरतलब है कि पिछले आम चुनाव में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन था। पार्टी तब ४० में से १७ सीटों पर चुनाव में उतरी थी और उसने १६ सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से जेडीयू इस बार भी १७ सीटों पर दावा कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जेडीयू १७ सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीटें मिलेंगी? सीट बंटवारे की घोषणा से पहले ही सीपीआई (माले) ने ५ सीटों पर दावा किया है, जबकि सीपीआई ३ सीटों पर लड़ने की बात कह रही है। वहीं १० सीटों की मांग कर रही कांग्रेस की इन दिनों जेडीयू से पटरी मेल नहीं खा रही है। टकराव का आलम यह है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने को लेकर कांग्रेस पर जेडीयू के नेता खुलकर हमला बोल रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू के कुछ नेता आरजेडी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। जिससे बिहार महागठबंधन में टकराव की आशंका जताई जा रही है। उधर, बीजेपी नेता नीतीश कुमार को लेकर नरम रुख दिखा रही है। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पार्टी के एक कार्यक्रम के लिए पटना में थीं। उन्होंने इस दौरान आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश को भगवान राम का वंशज करार दे दिया।

नयार पर प्रहार

गत् वर्ष संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने नयार नदी के नाम पर बनाई गई लघु फिल्म को देश का प्रथम पुरस्कार दिया था। यह फिल्म गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ रखने की थीम पर बनाई गई है। लेकिन उत्तराखण्ड का लोक निर्माण और वन विभाग इस थीम के उलट काम कर रहे हैं। सड़क निर्माण का मलबा सीधे नयार नदी में डालकर डंपिंग जोन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह तब है जब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी इस संबंध में सख्त निर्देश दे चुके हैं। नियमों और निर्देशों को वन विभाग कितनी गंभीरता से लेता है इसे एक अधिकारी की उस टिप्पणी से भी समझा जा सकता है जिसमें वह विकास की दुहाई दे नयार में मलबा डालने को जायज ठहरा रहे हैं

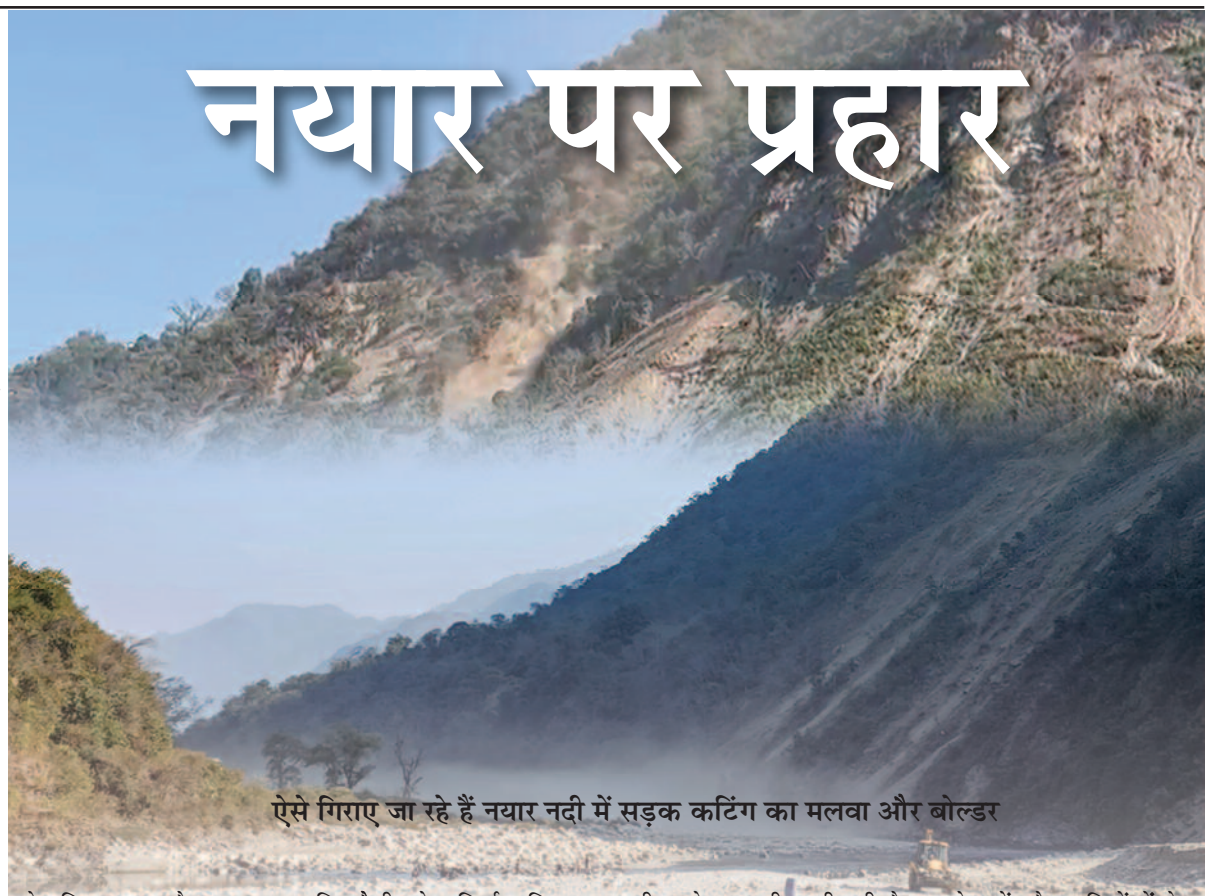

ऐसे गिराए जा रहे हैं नयार नदी में सड़क कटिंग का मलवा और बोल्डर

कृष्ण कुमार
krishanèkumar@thesundaypostèin

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखण्ड से खास लगाव रहा है। इसी लगाव के चलते उनके विजन में प्रदेश के विकास के लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और गंगा को स्वच्छ तथा निर्मल करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम में गंगा और उसकी सहायक नदियों को इससे जोड़ा गया है जिससे इन गैर ग्लेशियर नदियों के सांस्कृतिक, आर्थिकी और जैव विविधता को बरकरार रखते हुए इन नदी घाटियों में विकास के कार्यों की रूपरेखा बनाई जा सके। इन सबके बावजूद दुर्भाग्य से उत्तराखण्ड प्रदेश के सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा ही प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को असफल करने का काम किया जा रहा है।

ताजा प्रकरण गंगा की सहायक नदी नयार से जुड़ा है। पौड़ी जिले के सतपुली बांघाट क्षेत्र में सड़क निर्माण के मलवे को सीधे नयार नदी में फेंका जा रहा है जिससे नदी को भारी नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही करीब ५०० मीटर का हरा-भरा जंगल भी मलवे की भेंट चढ़ चुका है। इसके चलते नयार नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है, साथ ही जलीय जीवों को खतरा पैदा हो चुका है।

उल्लेखनीय है कि जिले के बंघाट के समीप लंगूर पट्टी के सीला ग्रामसभा के गूईन गाड़ से नैनी मोटर मार्ग के लिए डेढ़ किमी सड़क काटी जा रही है। यह सड़क नयार नदी के ठीक ऊपर सैकड़ों फीट ऊंचाई में बनाई जा रही है। 'दि संडे पोस्ट' ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया कि इसके निर्माण में निकाले गए बड़े-बड़े बोल्डर और मलवे को सीधे नयार नदी में फेंका जा रहा है जिससे मलवे और बोल्डर के कारण यहां लगभग आधा किलोमीटर का वन क्षेत्र पूरा का पूरा समाप्त होकर लैंड स्लाईडिंग जोन में तब्दील हो चुका है। इसके कारण न सिर्फ नयार नदी में मलवे के गिराए जाने से प्रदूषण बढ़ा है, साथ ही 'हिमालयन ट्राउड' और 'महाशीर' जैसी नदियों को स्वच्छ रखने वाली मछली की प्रजाति पर भी भारी संकट पैदा हो चुका है।

यही नहीं सीला ग्रामसभा के गूईन गाड़ से बडेल गांव के साथ -साथ करीब दो दर्जन गांवों का आवागमन का एक मात्र पैदल मार्ग में सड़कों के बोल्डर और मलवे गिराए जाने से कई स्थानों पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हैरत की बात यह है कि महज एक-डेढ़ माह पूर्व लाखों की लागत से इसकी मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा करवाया गया है।

ऐसा नहीं है कि पौड़ी लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों की घोर उदासीनता के चलते नयार नदी को मलवे का डंपिग जोन बनाए जाने का मामला पहली बार देखने में आया है। तकरीबन हर सड़क जो नयार नदी घाटी में बनाई गई है उसके द्वारा मलवे को नयार नदी में ही डाला जाता रहा है। देवप्रयाग सतपुली मोटर मार्ग हो या ब्यासघाट से डांडा नागराजा को जोड़ने वाली सड़क मार्ग के निर्माण का मामला हो, हर सड़क का मलवा डंपिंग जोन में फेके जाने की बजाय सीधे नयार नदी में ही डाला गया है। आज भी देवप्रयाग सतपुली मोटर मार्ग के निर्माण के घाव इस ४२ किमी लंबी सड़क पर साफ देखे जा सकते हैं कि किस तरह से इन सड़कों के निर्माण में ठेकदारों को लाभ पहुंचाने के लिए नयार नदी को तो बर्बाद किया ही है, साथ ही हजारों हेक्टेयर वन भूमि को भी वृक्षविहीन किया गया है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे 'दि संडे पोस्ट' संवाददाता को ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा सीधे फोन किया गया और बताया गया कि पौड़ी लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार को कहा गया है कि वे संवाददाता से बात कर ले क्योंकि वे इस मामले में कुछ शिकायत कर रहे हैं। इससे साफ है कि पौड़ी लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के ठेकेदार पर नियमानुसार काम करने का आदेश देने की बजाय सवांददाता से बात करने का आदेश दिया गया जो कि स्पष्ट तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि लोक निर्माण विभाग किस तरह से निर्माण के कार्य करने वाले ठेकेदारों के हित में काम कर रहा है।

अब नयार नदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में शामिल है, की बात करें तो पौराणिक नारद गंगा नदी जिसे नयार नदी कहा जाता है। देव प्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद गंगा नदी बनती है। इसी गंगा नदी की सबसे पहली गैर हिमानी सानी ग्लेशियर सदानीरा नयार नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दुधातोली पर्वत श्रृंखला से एक साथ दो नदियां पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी निकलती है जो सतपुली के बड़खोलू दुनाव में एक साथ मिलकर बड़ी नदी का स्वरूप लेकर करीब तीस किमी. की यात्रा करके ब्यास घाट में गंगा में मिल जाती है।

प्राचीनकाल से ही नयार नदी गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जीवन रेखा मानी जाती रही है। इसके तटों और घाटियों में बेहद उपजाऊ कृषि भूमि के साथ-साथ घने जंगल और अनेक जड़ी-बूटियों की भरमार रही है। ब्रिटिशकाल में नयार नदी को खास महत्व इसीलिए मिला कि तत्कालीन बिटिश गढ़वाल समूचे जिले को खाद्यान्न की आपूर्ति इन्हीं दोनों नयार नदियों की उपजाऊ जमीनों से होती थी। नयार नदी के तट पर बांघाट प्राचीनकाल से ही एक ढाकर मार्ग प्रचलित रहा है जिसका उल्लेख एटकिन्सन ने भी अपने हिमालयन गजेटियार में किया है।

नयार नदी अपनी जैव विविधता और विशेष क्षेत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसका प्रमाण इस बात से ही मिल जाता है कि इस नदी में 'हिमालयन ट्राउड' प्रजाति और 'महाशीर' मछलियों की प्रजातियों का सबसे बड़ा केंद्र है। जबकि यह नदी अन्य बड़ी नदियों के समान किसी ग्लेशियर से उत्पन्न नहीं है बावजूद इसके जल में जलीय जीवों की प्रचुर भरमार रही है। स्वयं मतस्य विभाग द्वारा इसमें हिमालयन ट्राउड को प्रजनन के लिए सफल प्रोजेक्ट चलाया जिसके चलते अब इस क्षेत्र में ट्राउड मछली का भरा पूरा संसार है। पर्यटन विभाग नयार नदी में हिमालयन ट्राउड के लिए एंगलिंग के लाइसेंस भी जारी हुए हैं।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा २६ सितंबर २०२३ को 'नदी गौरव कार्यक्रम' के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संस्कृति एवं कला केंद्र नई दिल्ली में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की बाबत स्वच्छता, पर्यावरण, जैव विविधता और आर्थिकी आजीविका तथा संस्कृति विषयक तीन दिवसीय सेमिनार आयोजित किया था जिसमें उत्तराखण्ड में चल रहे गांगा नदी की स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत भारत की विभिन्न नदियों के ऊपर बनाए गए भित्ती चित्रों, लघु फिल्मों को प्रसारण किया गया। इन प्रसारित लघु फिल्मों में पौड़ी के युवा प्रणेश असवाल एव प्रज्ञा सिंह रावत द्वारा नयार नदी पर बनाई गई ७ मिनट की लघु फिल्म को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म की थीम गंगा नदी को स्वच्छ रखने से पहले गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ रखने और इन नदियों की आर्थिकी, सामाजिकी तथा जैव विधिता का अक्षुण्ण रखते हुए योजनाएं बनाने पर जोर दिया गया, साथ ही जब तक सहायक नदियों को स्वच्छा नहीं रखा जाएगा तब तक गंगा नदी को स्वच्छ नहीं रखा जा सकता को प्रमुखता से उठाया गया।

हैरत की बात यह है कि सितंबर २०२३ को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा गंगा की सहायक नदियों को स्वच्छ रखने की थीम पर लघु फिल्म नयार नदी को प्रथम पुरस्कार तो देती है लेकिन उसी उत्तराखण्ड प्रदेश का लोक निर्माण और वन विभाग महज दो माह में ही नयार नदी को ही बर्बाद करने के काम में जुट जाता है। सड़क निर्माण का मलवा सीधे नयार नदी में डाले जाने पर लोक निर्माण विभाग हैरतनाक चुप्पी साधे हुए है और इसके लिए जिला योजना के बजट को दोष दे रहा है जबकि वन विभाग जिसका आधा किमी. का वन क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, वह भी इसे सामान्य बात मान चुप्पी साधे हुए है। जबकि इस क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का काम भी द्रुत गति से चल रहा है और रेलवे द्वारा मलवे को यानित डंपिंग जोन में ही गिराया जा रहा है। इसके विपरीत लोक निर्माण विभाग वर्षों से नयार नदी को डंपिंग जोन बनाने का काम कर रहा है। जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्माण का मलवा किसी भी सूरत में नदी-नालों में नहीं गिराया जा सकता, अगर कोई ऐसा करता है तो वह सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना का मामला बन जाता है।

बात अपनी-अपनी

आप बता रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग पौड़ी इस सड़क जिला योजना की सड़क है, तो इसके बारे में डीएम पौड़ी से आपको बात करनी चाहिए। मैं तो राज्य योजना से संबंधित सड़कों के बारे में बता सकता हूं, लेकिन अगर सड़क निर्माण का मलवा नदी में डाला जा रहा है तो यह गलत है, बगैर अनुमति के इस प्रकार से मलवा नदियों में नहीं डाला जा सकता।

पंकज कुमार पांडे, सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

आपने मेरे संज्ञान में ये मामला दिया है, मैं इसकी जानकारी लेता हूं। अगर मामला ऐसा है कि नयार नदी में सड़क कटिंग का मलवा डाला जा रहा है तो निश्चित ही नियम अनुसार कार्यवाही होगी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में गंगा नदी के साथ-साथ गंगा की सहायक नदियों को भी शामिल किया गया है। इसलिए ऐसी नदियों को भी स्वच्छ और निर्मल करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

रणवीर सिंह चौहान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड

मैं छुट्टी पर हूं। बाद में बात करूंगा।

सुशांत पटनायक, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल

इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी और यथोचित कार्यवाही भी होगी।

आशीष चौहान, जिलाधिकारी, पौड़ी

यह सड़क जिला योजना से स्वीकृत है और जिला योजना में ज्यादा बजट नहीं होता है इसलिए जिला योजना के कामों को ठेकेदार मनमर्जी से काम करते हैं। हर सड़क की डीपीआर में डंपिंग जोन आवश्यक है लेकिन जिला योजना में डंपिंग जोन का नियम नहीं होता और मलवा जहां सुविधा हो वहीं डाल दिया जाता है।

विवेक कुमार, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग पौड़ी

जब सड़क बनेगी तो मलवा तो निकलेगा ही और उसे कहीं न कहीं तो फेका ही जाएगा। विकास चाहिए तो यह होगा ही। जरूरी नहीं है कि वह वन क्षेत्र हो।

नलिन पंत, लैंसडॉन वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी

इतिहास के आइने में द्वाराहाट

द्वाराहाट को स्थानीय भाषा में स्वर्ग का मार्ग यूं ही नहीं कहा जाता है। यहां पांडवों के स्वर्ग जाने के रास्ते में बनी पांडुखोली तो है ही साथ ही कई ऐतिहासिक इमारतों का समावेश है। इस शहर को कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है क्योंकि यहां 365 मंदिरों का एक अद्भुत समूह है। द्वाराहाट के इन मंदिर समूह से हम पूरे उत्तराखण्ड के प्राचीन राजनीतिक इतिहास को समझने की एक रोशन खिड़की पाते हैं, वह खिड़की है जो उत्तराखण्ड के विगत 14 सौ वर्ष का क्रमबद्ध इतिहास दिखाती है

प्रमोद शाह

लेखक उत्तराखण्ड पुलिस में उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं।

द्वाराहाट उत्तराखण्ड के उन प्राचीनतम कस्बों में है, जिसकी पहचान और उपस्थिति इतिहास के हर दौर में किसी न किसी रूप में रही है। उत्तराखण्ड के अधिकांश लोग इस कस्बे से परिचित हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, यहां के भव्य प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि द्वाराहाट में ३६५ मंदिर और ३६५ ही नौलों का निर्माण नवी और दसवीं शताब्दी में कत्यूरी राजा बसंत देव और खर्पर देव द्वारा किया गया।

यह अधिकांश मंदिर एकल मंदिर के स्थान पर समूह के रूप में बनाए गए हैं। सर्वाधिक मंदिर जो १२ की संख्या में है वह 'कचहरी मंदिर' समूह में है। कचहरी मंदिर के साथ ही कत्यूरी राजाओं ने अपने पूर्वज रतन देव और गुर्जर देव के नाम से भी यहां मंदिर समूह स्थापित किए हैं।

द्वाराहाट के इन मंदिर समूह से हम पूरे उत्तराखण्ड के प्राचीन राजनीतिक इतिहास को समझने की एक रोशन खिड़की पाते हैं, वह खिड़की है जो उत्तराखण्ड के विगत १४ सौ वर्ष का क्रमबद्ध इतिहास दिखाती है।

जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखण्ड या यूं कहें हिमालय क्षेत्र का प्राचीन और शक्तिशाली राजवंश कत्यूर जो कि सूर्यवंशी राजा थे, अपनी समृद्धि के दिनों में यह राजवंश न केवल उत्तराखण्ड बल्कि पड़ोसी राज्य हिमाचल की कांगड़ा, किन्नौर और नेपाल तक भू फैला था। कत्यूरी राजा जो कि शिव भक्त और धर्म परायण थे, लेकिन सूर्यवंशी राजा होने के कारण इनके द्वारा निर्मित मंदिरों में सूर्य चक्र अनिवार्य रूप से स्थापित किया गया है। कटारमल अल्मोड़ा में तो सूर्य का मंदिर समूह भी है। उत्तराखण्ड में प्राचीन नागर शैली के इन मंदिरों में जोशीमठ का नरसिंह मंदिर, गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर तथा रुद्रनाथ, तुंगनाथ सहित पंच केदार ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर आदि बद्री का मंदिर समूह, जागेश्वर मंदिर समूह अधिक प्रसिद्ध हैं। यह भव्य और विराट मंदिर कत्यूरी राज्य की समृद्धि को भी दर्शाते हैं।

बेसाल्ट के बड़े-बड़े पत्थरों को काटकर बनाए गए यह विशाल मंदिर, जिनकी बाह्य दीवारों पर शानदार मूर्तिकला का प्रदर्शन है जो अधिकांशतः गांधार शैली में देखी जाती है। पहली ही नजर में कत्यूरी राजवंश द्वारा निर्मित इन मंदिरों जिनका निर्माण आठवीं, नवीं, दसवीं शताब्दी तक किया गया है, उनमें एक सामानता है। यह नागर शैली के मंदिर हैं। कुछ मंदिरों में कलश पर स्थानीय प्रयोग किए गए हैं।

मूर्ति निर्माण और मंदिर निर्माण की यह शैली औरंगाबाद (महाराष्ट्र) की एलोरा के मंदिर समूहों से मिलती है जो कि राष्ट्रकूट नरेशों द्वारा निर्मित हैं, जिनका निर्माण वर्ष छठी से आठवीं शताब्दी तक है। मंदिर और मूर्ति कला की यह सामानता राष्ट्रकूट नरेशों और कत्यूरी राजाओं के नजदीकी संबंध को दर्शाती है जिनके मध्य वैवाहिक संबंध होने के संकेत मिलते हैं।

कत्यूरी राजवंश जिसकी प्रारंभिक राजधानी पैन-खंडा (जोशीमठ) थी। इस सुदूर हिमालय क्षेत्र में राजधानी दो कारणों से स्थापित थी, एक हिमालय की विराटता से प्राप्त भौगोलिक सुरक्षा, दूसरा तिब्बत के महत्वपूर्ण लाभकारी व्यापार पर पकड़।

कत्यूर राजा अपने विशाल एवं दुर्गम हिमालयी राज्य पर शासन अपने सशक्त क्षत्रपों द्वारा संचालित करते थे। अकेले पौड़ी गढ़वाल में ५२ गढों का उल्लेख हमें मिलता है।

आठवीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ में उत्तर के धाम की स्थापना किए जाने के बाद से इस क्षेत्र में शेष भारत का रुझान तेजी से बढ़ा जिसका लाभ स्थानीय गढ़ों ने आपस में गोलबंदी कर कत्यूरी राजा के विरुद्ध दबाव बनाने में किया। पैन-खंडा के नजदीकी चांदपुर गढ़ी और बधानगढ़ी के क्षत्रपों की गोलबंदी ने कत्यूरी राजा वसुदेव को ८४९ ई. तक शासक था, उसके बाद कत्यूरी शासक बसंत देव और खर्पर देव को ८८० ई तक दबाव रखा, चांदपुर गढ़ी के क्षत्रप ने बद्रीनाथ यात्रा पर पहुंचे मध्य प्रदेश के गहरवार वंश के राजकुमार कनक पाल से अपनी बेटी का विवाह कर, उन्हें यहीं राज्य करने का निमंत्रण दिया, इस प्रकार ८८९ ईसवीं में राजा कनक पाल ने टिहरी के परमार वंश की नींव उत्तराखंड के में डाली।

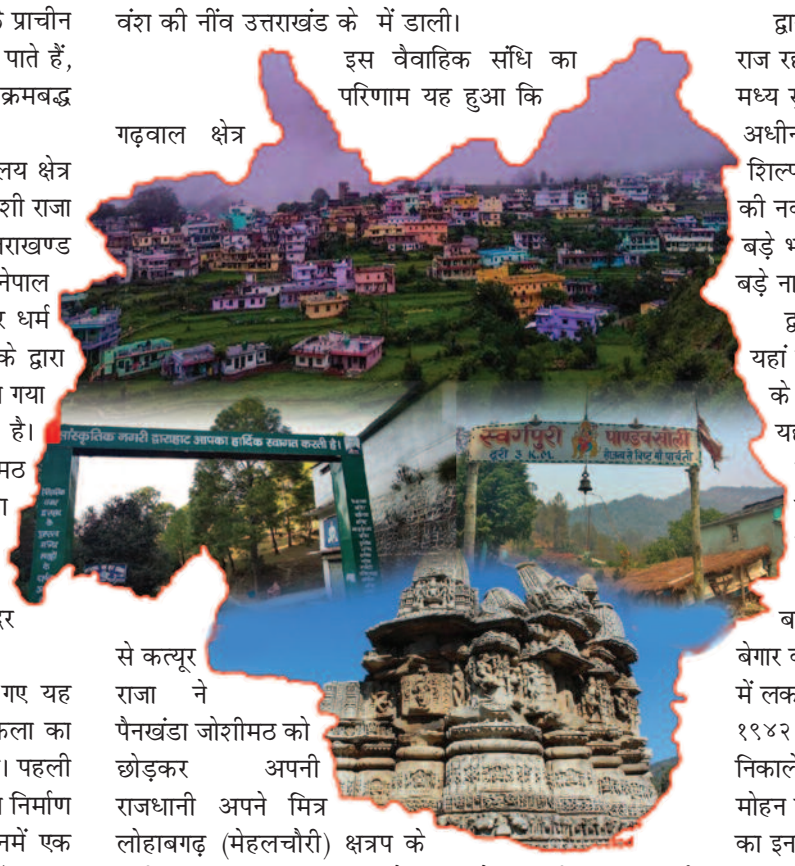

इस वैवाहिक संधि का परिणाम यह हुआ कि गढ़वाल क्षेत्र से कत्यूर राजा ने पैनखंडा जोशीमठ को छोड़कर अपनी राजधानी अपने मित्र लोहाबगढ़ (मेहलचौरी) क्षत्रप के समीप रामगंगा तट विराटनगर चौखुटिया में बना ली, यह अस्थाई ठिकाना था। राजधानी की तैयारी एक समतल और सुंदर भौगोलिक क्षेत्र द्वारिकापुरी अर्थात द्वाराहाट में हो रही थी। जहां ३६५ मंदिर और ३६५ नौले भव्य राजधानी के लिए तैयार हो रहे थे।

लेकिन उसके बाद भी कोई नदी न होने के कारण पानी की कमी की आशंका के चलते द्वाराहाट को कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ। अब राजधानी कोसी नदी के तट लखनपुर रामनगर पहुंच गई, जहां का मौसम कत्यूरों को रास नहीं आया तो कत्यूर फिर भागते हुए कार्तिकेयपुर बैजनाथ पहुंचे।

कत्यूर वंश जब आठवीं, नौवीं शताब्दी में कमजोर पड़ रहा था तो इसी वक्त राज्य की दक्षिण पूर्वी सीमा से चंदेल वंशी शासक सोमचंद ने राज्य में घुसपैठ की और चंपावत को अपनी राजधानी बना यहां चंद वंश का राज्य स्थापित किया। चंद कमजोर पड़ते कत्यूरी शासन में लगातार विस्तार करते रहे। इस दो तरफा दबाव से कत्यूरी शासन अंततः अस्कोट पिथौरागढ़ पहुंचकर पाल, संभल, देव, शाही, पांच शाखों में टूट गया।

चंद राजाओं की राजधानी उद्यान चंद और कल्याण चंद ने १५६० के आस-पास अल्मोड़ा स्थानांतरित की। तब से टिहरी के परमार वंश के साथ छोटे-छोटे अंतर में लगातार सीमा पर संघर्ष रहा। १७०९ में जगत चंद ने श्रीनगर को जीत लिया तो अगले ही वर्ष१७१० में फतेह शाह ने बहादुर सेनापति, पुरिया नैथानी के नेतृत्व में चंद राजा जगत चंद को बुरी तरह पराजित किया और द्वाराहाट क्षेत्र तक कब्जा कर लिया, पास में ही नैथाना गांव में ५०० सैनिकों का मजबूत किला बनाया। नैथना गांव आज भी सेनापति पुरिया नैथानी की बहादुरी की गाथा सुनाता है।

द्वाराहाट क्षेत्र में थोड़े समय तक टिहरी के शासकों का भी राज रहा। क्षेत्र अशांत रहा, बाद में प्रदीप शाह और दीपचंद के मध्य सुलह के बाद द्वाराहाट क्षेत्र स्थाई रूप से चंद शासकों के अधीन आया, इस संधि के बाद बेरीनाग के टम्टा और काष्ट शिल्पी आर्य, गढ़वाल राज्य पहुंचे और ताम्र उद्योग तथा लकड़ी की नक्काशी में काष्ट शिल्प ने यहां खूब विकास किया, गांव में बड़े भवन और बाखली का चलन बडा, कुमाऊं क्षेत्र के घरों में बड़े नारायण द्वार के विपरीत यहां तिबारी अधिक लोकप्रिय हुई।

द्वाराहाट जो कि १८वीं और १९वीं सदी में शांत बना रहा, यहां संस्कृति और आर्थिकी ने खूब तरक्की की १९वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही पट्टी व्यवस्था लागू होने के साथ द्वाराहाट का यह गौरवपूर्ण क्षेत्र तीन पट्टियों में विभक्त हुआ और यहां द्वाराहाट के गौरव को रेखांकित करता हुआ स्याल्दे, बिखौती का मेला लगातार लोकप्रिय होकर स्थानीय अस्मिता का प्रतीक बन गया।

द्वाराहाट क्षेत्र में सामाजिक चेतना का उभार लगातार बना रहा, जिसके परिणाम स्वरूप जब १९२०-२१ में कुली बेगार का आंदोलन बागेश्वर से चला तो अंग्रेजों को द्वाराहाट क्षेत्र में लकड़ी कटान और ढुलान के लिए यहां कोई बेगार नहीं मिली। १९४२ में 'भारत छोड़ो आंदोलन' के समय यहां बड़े जुलूस निकाले गए। यहीं के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मदन मोहन उपाध्याय के ऊपर उत्तराखण्ड का सबसे बड़ा १००० रुपए का इनाम अंग्रेज सरकार ने रखा, लेकिन वह फिर भी अंग्रेजों की गिरफ्त से बचकर मुंबई में झावेरी ब्रदर्स तथा उषा मेहता आदि के साथ मिलकर गुप्त आजाद रेडियो को संचालित करने लगे। इनके अतिरिक्त हरिदत्त कांडपाल, इंद्रलाल शाह, रामसिंह बिष्ट, भोलादत्त पांडे, भवानी दत्त, गुसाईं सिंह रावत, गंगादत्त फुलारा आदि सहित ५० से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस क्षेत्र में हुए।

इस प्रकार द्वाराहाट से हमें लगभग १४०० वर्ष का जीवंत और गौरवपूर्ण इतिहास मिलता है। यहां एक ऐसी शानदार रोशन खिड़की हमें मिलती है जिसके आलोक में हम उत्तराखण्ड के इतिहास को भी आसानी से समझ सकते हैं।

(लेखक की फेसबुक वाल से)

'दि संडे पोस्ट' द्वारा प्रकाशित किए जा रहे दुग्ध एवं डेयरी विभाग के घपले-घोटालों की हकीकत सामने आने लगी है। खुद शासन ने भ्रष्टाचार में आरोपित अधिकारियों पर कार्रवाई करके इसकी पुष्टि की है। विभाग की भ्रष्टाचार पर शह को इससे समझा जा सकता है कि 4 जनवरी 2023 को आंचल दूध के सैंपल की जांच की गई और उसमें सेहत के लिए हानिकारक मेलामाइन पाया गया। आरोपित अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाती तो दूध में मिलावटखोरी के इस धंधे पर रोक लगाई जा सकती थी। लेकिन विभाग इस पर रहस्मय चुप्पी साधे रहा। जिसका खामियाजा लोगों को दूध में मेलामाइन की मिलावट के रूप में भुगतना पड़ा है। मेलामाइन की मिलावट से कई गंभीर रोगों की उत्पत्ति होती है। 2008 में मेलामाइन की मिलावट से लाखों बच्चे और जानवर बीमारी की चपेट में आ गए थे। इस घटना को 'चाइनीज मिल्क स्कैंडल' के नाम से जाना जाता है

आंचल पर आंच

आकाश नागर
akash@thesundaypostèin

भारत में श्वेत-क्रांति का जनजागरण अभियान वर्षों से चलाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें दूध का उत्पादन बढ़ाने को लेकर सार्थक दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उत्तराखण्ड सरकार भी इस तरफ आगे बढ़ने का सार्थक प्रयास कर रही है। सरकारी अधिपत्य वाली आंचल डेयरी के उत्पाद उपभोक्ताओं को गुणवत्ता मुक्त मिले इसके लिए दुग्ध संघ से लेकर डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई है। मगर प्रदेश में दूध की उपलब्धता, मांग और बिक्री में बहुत अंतर है। ऐसे में मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर मिलावट होने की बात सामने आ रही है। गत दिनों दो अधिकारियों पर हुई कार्रवाई इसकी तस्दीक करती है कि प्रदेश में मिलावट खोरी का धंधा बेधड़क जारी है।

मिलावटखोरी पर उम्र कैद की सजा

मिलावट दूध में हो या शहद में, खाद्यान में हो या दवाइयों में सेहत के साथ खिलवाड़ का अक्षम्य अपराध तो है ही साथ ही ऐसे अपराधों में संलिप्त लोगों के लिए कठोर कार्यवाही का भी प्रावधान है। मिलावटखोरी करने वालों को कानून के तहत अधिकतम छह साल की सजा हो सकती है। इस कानून को नाकाफी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय की केएस राधाकृष्णन और एके सीकरी की पीठ ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि जिन राज्यों ने मिलावट के अपराध के लिए अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया हुआ है, वे इसे सख्ती से लागू करें।

दागदार हुआ आंचल/भाग-3

देश में ६९ प्रतिशत दूध मिलावटी

मिलावट के खिलाफ अनेक कठोर कानून होने के बावजूद मिलावट करने वालों को कोई डर नहीं रहता। आमतौर पर निजी कंपनियों वाले मिलावट करते रहते हैं, लेकिन उत्तराखण्ड दुग्ध सहकारी संघ द्वारा भी मिलावट करने का समाचार मिलना आश्चर्यचकित कर देने वाला है। एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक देश का लगभग उनहत्तर प्रतिशत दूध मिलावटी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मुताबिक देश में कृत्रिम और मिलावटी दूध का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। प्रदेश में इस मामले में लचीलापन सामने आया है। गत वर्ष दूध में मेलामाइन और एल्कोहल का मिलना और कार्यवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती करना प्रदेश के दुग्ध एवं डेयरी विभाग को कठघरे में खड़ा कर रहा है।

दो अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

पहली कार्रवाही दुग्ध संघ शिकारपुर (हरिद्वार) के डेयरी इंचार्ज राजेंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर हुई है। उत्तराखण्ड के अपर सचिव सुरेश चंद्र जोशी द्वारा इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विकास विभाग हल्द्वानी (नैनीताल) को दिए गए आदेशों में एफटीआई मशीन के आंकड़ों के विपरीत दुग्ध समितियों की ट्रैक सीट में फैट एवं एसएनएफ की मात्रा बढ़ाकर दुग्ध समितियों को अवैध लाभ पहुंचाए जाने की पुष्टि की है। जिसके आधार पर अपर सचिव सुरेश चंद्र जोशी ने डेयरी विकास निदेशालय में उपनिदेशक डीपी सिंह को १२ जनवरी २०२४ को उनके दायित्वों से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है।

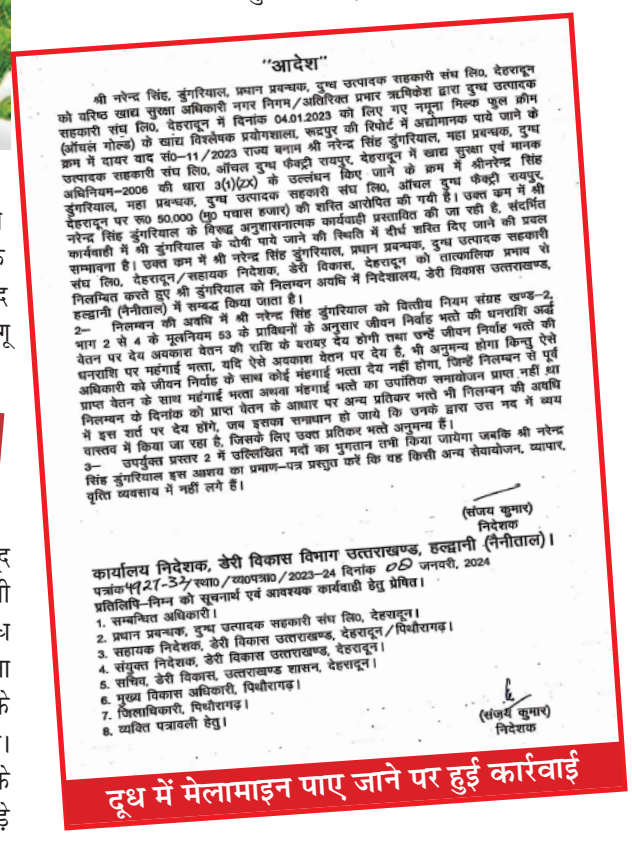

"आदेश"

श्री नरेन्द्र सिंह, डुंगरियाल, प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, देहरादून को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम/अतिरिक्त प्रभार ऋषिकेश द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, देहरादून में दिनांक 04.01.2023 को लिए गए नमूना मिल्ख फुल क्रीम (आँचल गोल्ड) के खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, रूद्रपुर की रिपोर्ट में अद्योमानक पाये जाने के क्रम में दायर वाद सं0–11/2023 राज्य बनाम श्री नरेन्द्र सिंह डुंगरियाल, महा प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, आँचल दुग्ध फैक्ट्री रायपुर, देहरादून में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 3(1)(ZX) के उल्लंघन किए जाने के क्रम में श्रीनरेन्द्र सिंह डुंगरियाल, महा प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, आँचल दुग्ध फैक्ट्री रायपुर, देहरादून पर रू0 50,000 (मु0 पचास हजार) की शस्ति आरोपित की गयी है। उक्त कम में श्री नरेन्द्र सिंह डुंगरियाल के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है, संदर्भित कार्यवाही में श्री डुंगरियाल के दोषी पाये जाने की स्थिति में दीर्घ शस्ति दिए जाने की प्रबल सम्भावना है। उक्त कम में श्री नरेन्द्र सिंह डुंगरियाल, प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, देहरादून/सहायक निदेशक, डेरी विकास, देहरादून को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए श्री डुंगरियाल को निलम्बन अवधि में निदेशालय, डेरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) में सम्बद्ध किया जाता है।

2– निलम्बन की अवधि में श्री नरेन्द्र सिंह डुंगरियाल को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूलनियम 53 के प्राविधनों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपांतिया समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

3– उपर्युक्त प्रस्तर 2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री नरेन्द्र सिंह डुंगरियाल इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

(संजय कुमार)
निदेशक

कार्यालय निदेशक, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
पत्रांक 4721-37/स्था0/व्या0पत्रा0/2023–24 दिनांक 08 जनवरी, 2024
प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सम्बन्धित अधिकारी।
2. प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, देहरादून।
3. सहायक निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, देहरादून/पिथौरागढ़।
4. संयुक्त निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, डेरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
7. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
8. व्यक्ति पत्रावली हेतु।

(संजय कुमार)
निदेशक

दूध में मेलामाइन पाए जाने पर हुई कार्रवाई

गुमराह कर रहे मुकेश बोरा

फोटो : मुकेश बोरा के फेसबुक से

मुकेश बोरा

नैनीताल दुग्ध सहकारी संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और डेयरी फेडरेशन के प्रशासक मुकेश बोरा को दूध में मेलामाइन पाए जाने के प्रकरण पर या तो पूरी जानकारी नहीं है या वह जानबूझकर गुमराह कर रहे है। उनका कहना है कि मेलामाइन मामले में रूद्रपुर वाली लेब की जांच रिपोर्ट से वह संतुष्ट नहीं है इसके चलते ही दूध के सैंपल की एक ओर जांच हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि दूध के सैंपल में मेलामाइन की दूसरी जांच रिपोर्ट भी कराई जा चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि दूसरी जांच रिपोर्ट में दूध में मेलामाइन की उपस्थिति पहली जांच रिपोर्ट से अधिक आई है।

देहरादून के अपर जिलाधिकारी राम जी शरण शर्मा ने। शर्मा द्वारा १८ अक्टूबर २०२३ को दिए गए एक आदेश में इस कृत्य के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड रायपुर (देहरादून) में महाप्रबंधक नरेंद्र सिंह डुंगरियाल को अधिनियम की धारा २६ एवं २७ का उल्लंघन में दोषी मानते हुए धारा ५१ के तहत दंडनीय अपराध माना है। इसी के साथ ५० हजार रूपये का अर्थदंड दुग्ध सहकारी समिति आंचल दुग्ध फैक्टरी रायपुर (देहरादून) से वसूल करने के आदेश दिए है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राम जी शरण शर्मा ने आपने आदेश में लिखा है कि "मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तर्को को सुना। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम देहरादून का तर्क है कि कारोबारकर्ता उक्त उत्पादक फुलक्रीम मिल्क (आंचल गोल्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-२००६ एवं विनियम २०११ के अनुरूप न होने के संदेह पर नियमानुसार नमूना खाद्य विश्लेषक रुद्रपुर भेजा गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त खाद्य पदार्थ आंचल गोल्ड मिल्क में मेलामाइन पदार्थ अधिकत २.५ के पीपीएम स्थान पर २.५८ पीपीएम पाया गया।

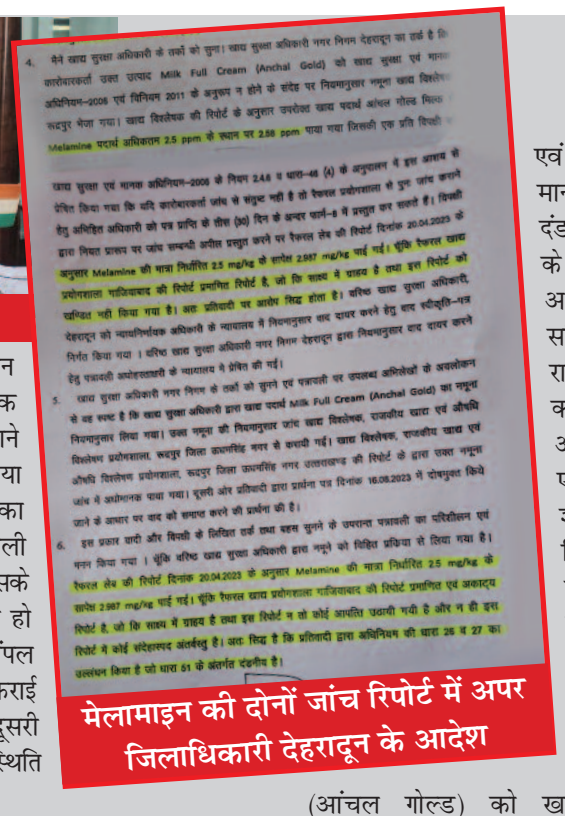

4. मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तर्को को सुना। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम देहरादून का तर्क है कि कारोबारकर्ता उक्त उत्पाद Milk Full Cream (Anchal Gold) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 एवं विनियम 2011 के अनुरूप न होने के संदेह पर नियमानुसार नमूना खाद्य विश्लेषक रूद्रपुर भेजा गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त खाद्य पदार्थ आंचल गोल्ड मिल्क Melamine पदार्थ अधिकतम 2.5 ppm के स्थान पर 2.58 ppm पाया गया जिसकी एक प्रति दिनांक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के नियम 2.4.6 व धारा–46 (4) के अनुपालन में इस आशय से प्रेषित किया गया कि यदि कारोबारकर्ता जांच से संतुष्ट नहीं है तो रैफरल प्रयोगशाला से पुनः जांच कराने हेतु अभिहित अधिकारी को पत्र प्राप्ति के तीस (30) दिन के अन्दर फार्म–6 में प्रस्तुत कर सकते हैं। विपक्षी द्वारा नियत प्रारूप पर जांच सम्बन्धी अपील प्रस्तुत करने पर रैफरल लेब की रिपोर्ट दिनांक 20.04.2023 के अनुसार Melamine की मात्रा निर्धारित 2.5 mg/kg के सापेक्ष 2.987 mg/kg पाई गई। चूंकि रैफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की रिपोर्ट प्रमाणित रिपोर्ट है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य है तथा इस रिपोर्ट को खण्डित नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी पर आरोप सिद्ध होता है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, देहरादून को न्यायनिर्णायक अधिकारी के न्यायालय में नियमानुसार वाद दायर करने हेतु शस्ति–पत्र निर्गत किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम देहरादून द्वारा नियमानुसार वाद दायर करने हेतु पत्रावली अपीलस्थापरी के न्यायालय में प्रेषित की गई।

5. खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ Milk Full Cream (Anchal Gold) का नमूना नियमानुसार लिया गया। उक्त नमूना की नियमानुसार जांच खाद्य विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर से करायी गई। खाद्य विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड की रिपोर्ट के द्वारा उक्त नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। दूसरी ओर प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2023 में दोषमुक्त किये जाने के आधार पर वाद को समाप्त करने की प्रार्थना की है।

6. इस प्रकार वादी और विपक्षी के लिखित तर्क तथा बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली का परिशीलन एवं मनन किया गया। चूंकि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने को विहित प्रक्रिया से लिया गया है। रैफरल लेब की रिपोर्ट दिनांक 20.04.2023 के अनुसार Melamine की मात्रा निर्धारित 2.5 mg/kg के सापेक्ष 2.987 mg/kg पाई गई। चूंकि रैफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की रिपोर्ट प्रमाणित एवं अकाट्य रिपोर्ट है, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य है तथा इस रिपोर्ट न तो कोई आपत्ति उठायी गयी है और न ही इस रिपोर्ट में कोई संदेहास्पद अंतर्वस्तु है। अतः सिद्ध है कि प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 26 व 27 का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय है।

मेलामाइन की दोनों जांच रिपोर्ट में अपर जिलाधिकारी देहरादून के आदेश

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ का नमूना नियमानुसार लिया गयां उक्त नमूना की नियमानुसार जांच खाद्य विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, रुद्रपुर जिला ऊधमसिंहनगर से करायी गई। खाद्य विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला, रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड की रिपोर्ट के द्वारा उक्त नमूना जांच में अधोमानक पाया गया। दूसरी ओर प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक १६/०८/२०२३ में दोषमुक्त किए जाने के आधार पर वाद को समाप्त करने की प्रार्थना की है।

इस प्रकार वादी और विपक्षी के लिखित तर्क तथा बहस सुनने के उपरांत पत्रावली का परिशीलन एवं मनन किया गया। चूंकि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने को विहित प्रक्रिया से लिया गया है। रैफरल लेब की रिपोर्ट दिनांक २०/०४/२०२३ के अनुसार डमसंउपदम की मात्रा निर्धारित २.५ एमजी/किलो ग्राम सापेक्ष २.९८७ एमजी किलोग्राम पाई गई। चूंकि रैफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की रिपोर्ट प्रमाणित एवं अकाट्य रिपोर्ट है, जो कि साक्ष्य में ग्रहय है तथा इस रिपोर्ट न तो कोई आपत्ति उठायी गयी है और न ही इस रिपोर्ट में कोइ संदेहास्पद अंतर्वस्तु है। अतः सिद्ध है कि प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा २६ व २७ का उल्लंघन किया है जो धारा ५१ के अंतर्गत दंडनीय है।"

इसके अलावा दूसरा मामला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड देहरादून के प्रधान प्रबंधक नरेंद्र सिंह डुंगरियाल का है। डुंगरियाल पर ऋषिकेश दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का भी अतिरिक्त प्रभार था। डुगरियाल पर डेयरी फेडरेशन के निदेशक संजय कुमार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जबकि ९ जनवरी २०२४ को डुगरियाल पर कार्यवाही करते हुए देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान द्वारा उन्हें सहायक निदेशक डेयरी विकास विभाग पिथौरागढ़ में योगदान करना सुनिश्चित किया है। इसी के साथ ही आंचल दुग्ध फैक्टरी रायपुर (देहरादून) पर भी ५० हजार का जुर्माना लगाया गया है।

डुंगरियाल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई ४ जनवरी २०२३ को लिए गए दूध के नमूने के आधार पर की गई है। यह नमूना आंचल गोल्ड के फुलक्रीम दूध का था जिसे रूद्रपुर की खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में जांचा गया। दूध के इस नमूने में हानिकारक पदार्थ मेलामाइन मानको से अधिक पाया गया था।

क्या होता है मेलामाइन

मेलामाइन एक कार्बन आधारित रसायन होता है जो आमतौर पर नाइट्रोजन से समृद्ध सफेद क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। व्यापक तौर पर मेलामाइन का प्रयोग प्लास्टिक, गोंद, काउंटरटॉप्स और व्हाइट बोर्ड आदि बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन बाद में इसे दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। कई बार दूध की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से उसमें पानी मिला देते हैं। जिससे दूध में प्रोटीन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इस प्रोटीन की मात्रा को संतुलित करने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया जाता है। कुछ जानवरों पर इस चारे को टेस्ट करने पर पता चला कि ये जानवरों को बीमार कर रहा था और कुछ जानवरों की मृत्यु का कारण भी बना।

चाइनीज मिल्क स्कैंडल

एक जानकारी के अनुसार चाईना के अलावा अमेरिका और साउथ अफ्रीका से भी जानवरों के किडनी फेलियर और मृत्यु की खबरें आई और इन सबका संबंध चाइना के मेलामाइन वाले ग्लूटीन से पाया गया। मार्च २००७ तक सैंकड़ों पालतू जानवरों की मृत्यु की खबरें आ चुकी थीं। कई अपुष्ट खबरों ने तो ये संख्या हजारों में बताई थी। कई देशों में उन उत्पादकों को वापस मंगाया गया जिनमें मेलामाइन की मिलावट पाई गई थी। यहां तक कि कनेडियन फूड कंपनी 'मेनू फूड' ने भी अपने प्रोडक्ट बाजार से वापस मंगा लिए थे। बताया जाता है कि चीन में तीन लाख से अधिक बच्चे इस दूध को पीकर बीमार पड़े थे जिसके चलते २००८ में चीन सरकार ने इस मिलावटखोरी को पकड़ लिया। इतिहास में इस घटना को २००८ 'चाइनीज मिल्क स्कैंडल' के नाम से जाना जाता है।

कितने मेलामाइन की है परमिशन

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने २०१६ में एक कानून बनाकर भारत में बिकने वाले दूध में मेलामाइन को कानूनी मान्यता दी थी। इसके अंतर्गत इंफेंट फॉर्मूला बनाने वाली कोई भी कंपनी अपने मिल्क पाउडर में १ मिलीग्राम मेलामाइन मिला सकती है। लिक्विड मिल्क में ये लिमिट १५ मिलग्राम/लीटर की है। बाकी सभी खाद्य पदार्थ में ये २.५ मिलीग्राम/किलो के हिसाब से मिलाया जा सकता है। जिसे गलत नहीं माना गया है। लेकिन इससे ऊपर एक माइक्रोग्राम की मात्रा में भी मेलामाइन का पाया जाना सेहत पर बहुत ही खतरनाक असर डालता है। **'दि संडे पोस्ट'** ने अपने अंक ३० में 'दागदार हुआ आंचल' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था जिसमें रूद्रपुर स्थित प्रयोगशाला का वह सबूत भी उजागर किया था जिसमें दूध का नमूना फेल हो गया था। इस नमूने में दूध में मेलामाइन की मात्रा २.८ पाई गई थी। मतलब यह कि जो मेलामाइन २.५ होना था वह २.८ तक पाया गया था।

दागदार हुआ आंचल/भाग-3

बात अपनी-अपनी

मेरा दुग्ध संघ और डेयरी विभाग से कोई नाता नहीं है। मैं नहीं जानता कि मेरे खिलाफ क्यों शिकायत की गई है।

आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव मुख्यमंत्री

हमारे यहां शिकायत प्रकोष्ठ है जिसमें शिकायतों का निपटारा किया जाता है। शिकातय की जांच कराने के बाद नियमानुसार उस पर कार्रवाई होती है। पोखरिया की शिकायत पर भी न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी।

अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड

दूध में मेलामाइन नहीं मिलाई जाती है। दूध में प्राकृतिक रूप से मेलामाइन होती है। वह २.५ तक होती है। रिपोर्ट में जो आई है वह २.५८ है। लैब में कभी-कभी ऊपर-नीचे हो जाता है। इतना बड़ा मामला नहीं है यह। रूद्रपुर लैब की रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं है। डुंगरियाल पर क्यों एक्शन हुआ यह आप संबंधित अधिकारी से पूछिए। अभी दूसरी जांच आनी बाकी है। पोखरिया द्वारा की गई शिकायत मेरी जानकारी में नहीं है। बीसी पोखरिया भ्रष्टाचारी है, वह बलात्कार के केस में जेल के अंदर जा चुका है। निकालनी है तो उनकी खबर लगाएं। मैं आज भी कह रहा हूं वह ब्लैकमेलर है। उसका तो धंधा है फर्जी आरोप लगाकर पैसा ऐंठने का।

मुकेश बोरा, निवर्तमान अध्यक्ष दुग्ध संघ नैनीताल एवं प्रशासक डेयरी फेडरेशन

सेहत पर मेलामाइन का हमला

वैज्ञानिक प्रयोगों में भी सिद्ध हो चुका है कि मेलामाइन एक बहुत खतरनाक किस्म का जहर है। इसकी माइक्रोग्राम मात्रा भी किडनी की कोशिकाओं को डैमेज कर नष्ट कर देती है। इससे किडनी फेल हो जाती है और तमाम तरह की अन्य बीमारियां लग जाती हैं। मेलामाइन के कण गुर्दों में जमा हो जाते हैं और सफेद टाइल्स के जैसी पथरी बनाते हैं। इसके संपर्क में आने वाली कोशिकाएं आरओएस नामक केमिकल बनाती है जो कैंसर पैदा करती है। दूध में मेलामाइन मिले होने की पहचान यह है कि धूप में रखने पर दूध का पैकेट फूलकर गुब्बारा हो जाता है।

मिलावटखोरी पर पुलिस में शिकायत

दुग्ध एवं डेयरी विभाग के भ्रष्टाचार पर मुखर होने वाले याचिकाकर्ता और समाजसेवी भुवन चंद्र पोखरिया ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को एक शिकायती पत्र सौंपा है। जिसमें उन्होंने आंचल दुग्ध फैक्ट्री पर दुग्ध में मेलामाइन एवं एल्कोहल मिलाने और जनता के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इसके लिए उन्होंने डेयरी विकास विभाग के वर्तमान मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित यूसीडीएफ के प्रशासक और दुग्ध संघ नैनीताल के निर्वतमान अध्यक्ष मुकेश बोरा, विभाग के सचिव डॉ. वीबीआर पुरुषोत्तम एवं आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुदंरम तथा नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं में सामन्य प्रबंधक निर्भय नारायण सिंह को सीधे तौर पर दूध में मिलावट कर मानव जीवन से स्वास्थ्य संबंधी खिलावाड़ करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सभी के खिलाफ आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

पढ़िए अगले अंक में नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं में दूध के टैंकरों में चोरी और घटतोली की कहानी।

पहाड़ों पर होगा पहला आधुनिक स्टेडियम

जसपाल नेगी

आगामी तीन फरवरी को पौड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहाड़ के पहले सुविधा सम्पन्न हाई आधुनिक स्टेडियम का शुभारंभ करेंगे। इस स्टेडियम में बॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन हॉल, टीटी हॉल, चार सौ मीटर सिंथेटिक ट्रैक, खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम सहित कई सुविधाएं होंगी जिसके बाद खेलों के आयोजन किए जाने की शुरुआत होगी। फलस्वरूप पहाड़ों के प्रतिभागी युवाओं को इस स्टेडियम के जरिए अपनी किस्मत आजमाने का मैदान मिलेगा

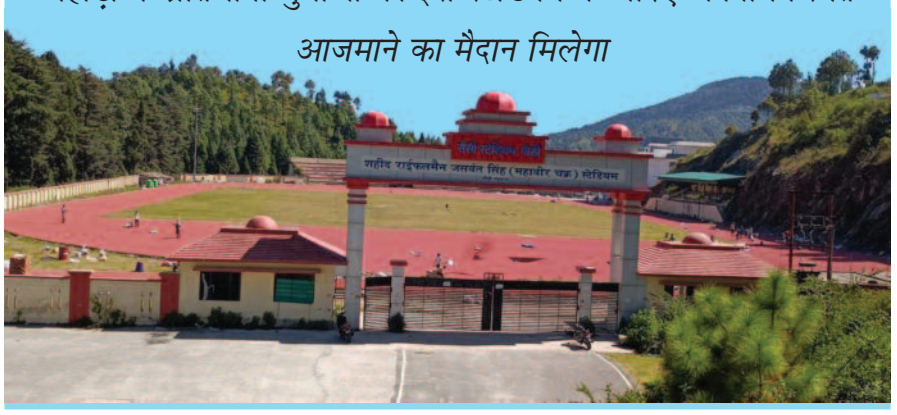

अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही पौड़ीवासियों को बहुआयामी स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। पौड़ी शहर के शीर्ष में स्थित रांसी स्टेडियम के विस्तारीकरण का कार्य काफी हद तक पूर्ण हो चुका है। पर्यटन नगरी पौड़ी का रांसी स्टेडियम जल्द ही बहुआयामी स्टेडियम के रूप में निखरा नजर आएगा। यहां विस्तारीकरण के रूप में होने वाले निर्माण कार्य करीब-करीब पूरे हो चुके हैं। खेल विभाग की मानें तो स्टेडियम का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और योजना कार्यदायी संस्था से खेल विभाग को भी स्थांतरण हो चुकी है।

पौड़ी शहर के शीर्ष में स्थित है रांसी स्टेडियम जहां हरे-भरे पेड़ों के बीच मैदान की सुंदरता देखते ही बनती है। वाहनों के माध्यम से आसानी से स्टेडियम तक पहुंचा जा सकता है। अभी तक इस खेल मैदान में सुविधाओं के अभाव में कभी स्थानीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता या फिर कभी शिक्षा विभाग की खेल प्रतियोगिताएं आदि जैसे कार्यक्रम ही आयोजित होते रहे हैं। इस सबके बीच सरकार ने स्टेडियम को संवारने और विस्तारीकरण की दिशा में हामी भरी तो उम्मीदों को भी पंख लगे। खेल स्टेडियम को आधुनिक बनाने के लिए २२ करोड़ से अधिक की धनराशि से इन दिनों कार्य किए जा रहे हैं।

जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट के अनुसार स्टेडियम के साथ-साथ बॉलीबॉल कोट, बैडमिटन हॉल, टीटी हॉल, चार सौ मीटर सिंथेटिक ट्रैक के अलावा खिलाड़ियों के लिए चैजिंग रूम, दर्शक दीर्घा का निर्माण कार्य हो चुका है। कार्य पूरा करवाने के लिए जिला प्रशासन और खेल विभाग जुटा हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि निमार्ण कार्य पूरे होने पर यहां खेल प्रतिभाएं अपनी किस्मत आजमाने को मैदान में उतरेंगी। रांसी स्टेडियम जिसका नाम शहीद राईफलमैन जसवंत सिंह रावत (महावीर चक्र) स्टेडियम भी रखा है। यह स्टेडियम गढ़वाल मंडल में देहरादून को छोड़ पहाड़ी जनपदों का पहला सुविधा संपन्न आधुनिक खेल मैदान में शामिल हो जाएगा।

पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने की थी घोषणा

२०२१ में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंडल मुख्यालय पौड़ी में स्थित रांसी स्टेडियम के विस्तारीकरण की घोषणा की थी। उन्होंने स्टेडियम को हाई एल्टीट्यूट सेंटर के रूप में तब्दील किए जाने की यह घोषणा अपने पौड़ी आगमन के दौरान की। तत्कालीन और मौजूदा भाजपा सरकार ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया तो धरातल पर धीरे-धीरे उम्मीदें जगने लगी हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कुछ माह पूर्व स्टेडियम का निरीक्षण किया था। गौरतलब है कि जब २०२२ में पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके द्वारा बहुउद्देश्यीय स्टेडियम को धनराशि आवंटित हुई थी। तब सीएम धामी ने दावा किया था कि २०२३ में इस स्टेडियम का कार्य पूरा हो जाएगा।

"रांसी स्टेडियम में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। रांसी स्टेडियम में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। प्रतिमा के लिए खेल विभाग को धनराशि भी मुहैया करा दी गई थी। यह प्रतिमा उनके अदम्य साहस और वीरता का संदेश भी देगी। स्टेडियम में आने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी मिलेगी। आगामी तीन फरवरी को मुख्यमंत्री बहुआयामी स्टेडियम व प्रतिमा का अनावरण करेंगे।"

डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी, पौड़ी

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 27 जनवरी, 2024

उत्तराखण्ड की 'ऐपण' गर्ल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं ऐपण गर्ल की स्टॉल, साथ में राज्यपाल गुरमीत सिंह एवं मंत्री धन सिंह रावत

अपने हुनर और सोच से लोककला को रोजगार से जोड़ना हो या फिर घर की देहरी से देश के फलक तक अपनी पारंपरिक लोककला को पहचान दिलाना हो, इसे कुमाऊं के छोई (रामनगर) की चेली ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती से सीखा जा सकता है। विगत पांच सालों से मीनाक्षी लोककला ऐपण को नई पहचान दिलाने और इसे रोजगार से जोड़ने की कयावद में लगी हुई हैं। मीनाक्षी की पहल से आज ऐपण कला देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी पहचान बना पाने में सफल हुई है। ऐपण से महिलाओं को अपने ही घर में रोजगार मिल रहा जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो रही हैं

संजय चौहान

उत्तराखण्ड के कुमाऊं मंडल में नैनीताल जनपद के रामनगर की रहने वाली मीनाक्षी अभी महज २५ साल की हैं। मीनाक्षी ने ऐपण कला की बारकिंया अपनी दादी और मां से सीखी। मीनाक्षी कहती हैं कि जब भी घर में मेरी दादी और मां ऐपण बनाती थी तो मैं बड़े ध्यान से देखती थी। मुझे बचपन से ही ऐपण कला आकर्षित करती थी और आज मैं भी ऐपण बनाने लगी हूं। ऐपण गर्ल ने अपने पूरे घर के कोने-कोने को ऐपण की खूबसूरती से सजाया है। जहां भी नजर पड़े आपको बेहतरीन चित्रकारी का नमूना दिखाई देगा। ये घर नहीं बल्कि चित्रकला का कोई म्यूजियम नजर आता है। लोगों का कहना है कि कुमाऊं की इस समृद्धशाली कला को महिलाओं ने ही जीवित रखा है। इस अनमोल धरोहर को सजाने, संवारने, सहेजने की जिम्मेदारी महिलाएं बरसों से बखूबी निभाती आ रही हैं। महिलाएं इस चित्रकला के माध्यम से अपने मन के भाव, अपनी शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति ईश्वर और अपने घर के प्रति करती हैं। इससे न सिर्फ घर सुंदर दिखता है बल्कि पवित्र भी हो जाता है। मन व माहौल एक नए उत्साह और उमंग से भर जाता है।

ऐपण का इतिहास

कुमाऊं में किसी भी मांगलिक कार्य के अवसर पर अपने -अपने घरों को सजाने की परंपरा है। ऐपण कुमाऊं की एक लोक चित्रकला की शैली है जो अपनी अलग पहचान बना चुकी है। परंपरागत ऐपण प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं जैसे गेरू (एक प्रकार की लाल मिट्टी जो पहाड़ में पाई जाती है) और चावल के आटे में पानी मिलाकर उसे थोड़ा पतला बनाया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में बिस्वार कहते हैं) से बनाई जाती है। इसमें महिलाएं विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर घर के आंगनों, दरवाजों, दीवारों, मंदिरों को सजाती हैं जिन्हें ऐपण कहते हैं। ऐपण का अर्थ लीपने से होता है और लीप शब्द का अर्थ अंगुलियों से रंग लगाना है। ऐपण बनाने वक्त महिलाएं चांद, सूरज, स्वस्तिक, गणेश जी, फूल,पत्ते, बेल बूटे, लक्ष्मी पैर, चोखाने, चौपड़, शंख, दिये, घंटी आदि चित्र खूबसूरती से जमीन पर उकेरती हैं। जिस जगह पर ऐपण बनाने होते हैं उस जगह की पहले गेरू से पुताई की जाती है उसके बाद उसमें बिस्वार से डिजाइन बनाए जाते हैं। दीपावली के अवसर पर कुमाऊं के घर-घर एपण से सज जाते हैं। घरों को आंगन से घर के मंदिर तक ऐपण देकर सजाया जाता है। दीपावली में बनाए जाने वाले ऐपण में मां लक्ष्मी के पैर घर के बाहर से अंदर की ओर बनाए जाते है। दो पैरों के बीच के खाली स्थान पर गोल आकृति बनाई जाती है जो धन का प्रतीक माना जाता है। पूजा कक्ष में भी लक्ष्मी की चौकी बनाई जाती है। माना जाता है कि इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर परिवार को धनधान्य से पूर्ण करती है। इनके साथ लहरों, फूल मालाओं, सितारों, बेल-बूटों व स्वास्तिक चिह्न की आकृतियां बनाई जाती हैं। अलग-अलग प्रकार के ऐपण बनाते समय अनेक मंत्रों का भी उच्चारण करने की परंपरा है। ऐपण बनाते समय कई त्योहारों पर मांगिलक गीतों का गायन भी किया जाता रहा है। गोवर्धन पूजा पर 'गोवर्धन पट्टा तथा कृष्ण जन्माष्टमी पर 'जन्माष्टमी पट्टे बनाए जाते हैं। नवरात्र में 'नवदुर्गा चौकी तथा कलश स्थापना के लिए नौ देवियों एवं देवताओं की सुंदर आकृतियों युक्त 'दुर्गा चौकी बनाई जाती है। सोमवार को शिव व्रत के लिए 'शिव-शक्ति चौकी बनाने की परंपरा है। सावन में पार्थिव पूजन के लिए 'शिवपीठ चौकी तथा व्रत में पूजा-स्थल पर रखने के लिए कपड़े पर 'शिवार्चन चौकी बनाई जाती है। ऐपण में लोगों की कलात्मक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है।

> पहले पहाड़ों में ऐपण कला किचन तक ही सीमित थी। लेकिन अब यह कला पहाड़ों से निकलकर शहरों तक पहुंच चुकी है। जीआई टैग मिलने के बाद यह देश में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने को तैयार है। लेकिन ऐपण कला को पेंटिंग के तौर पर अपनाकर इसे पारंपरिक रूप से आगे बढ़ाना होगा। मैं चाहती हूं कि यह कला सिर्फ लाल-सफेद तक ही न सिमटकर रहे।
>
> ***मीनाक्षी खाती, ऐपण गर्ल रामनगर***

अन्य प्रदेशों में अलग-अलग नामों से जानी जाती है ऐपण

रंगो और कूची की इस कला को उत्तराखण्ड के कुमाऊं क्षेत्र में ऐपण नाम से जाना जाता है। वहीं केरल में कोल्लम, बंगाल त्रिपुरा व आसाम में अल्पना, उत्तर प्रदेश में साची और चौक पुरना, बिहार में अरिपन, आंध्र प्रदेश में मुग्गु, महाराष्ट्र में रंगोली और राजस्थान में इस कला को मॉडला के नाम से जाना जाता है। सभी कलाओं में रंगो से चित्रकारी की जाती है।

दिल्ली के राजपथ से लेकर कांस के रेड कार्पेट तक ऐपण डिजाइन की धूम

२६ जनवरी २०२३ को गणतंत्र दिवस की परेड में पूरा देश उत्तराखण्ड की लोककला ऐपण से रू-ब-रू हुआ था। कर्तव्यपथ पर जब उत्तराखण्ड की झांकी निकली तो ऐपण की चौकियों व बेलों के चटक रंग ने पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित किया गए। झांकी में ऐपण के डिजाइन ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती से लिये गये थे। झांकी के आगे और पीछे उत्तराखण्ड का नाम भी ऐपण कला से लिखा गया था। मानसखंड थीम पर आधारित उत्तराखण्ड की झांकी ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जबकि मई महीने में सात समंदर पार अभिनेता अभिलाष थपलियाल ने उत्तराखण्ड की पारंपरिक पोशाक में कांस फिल्म महोत्सव में प्रतिभाग किया था। अभिलाष ने ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती के मीनों तिरू द ऐपण प्रोजेक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित एक ऐपण मोटिफ शॉल लपेटा था और कांस के रेड कारपेट पर उत्तराखण्ड की लोक कला ऐपण को वैश्विक पहचान दिलाई।

ऐपण के ये उत्पाद बनाती है मीनाक्षी

मीनाक्षी अपने मीनाकृति द ऐपण प्रोजेक्ट के जरिए ऐपण से बने कोस्टर, टी सैट, ऐपण कला से सजे अल दैनिक जीवन की चीजें, की चौन, नेम प्लेट, ऐपण राखी, कैलेंडर, डायरी, काफी मग, करवा चौथ की थाली, दीपावली की थाली, ऐपणकला में रंगे दीपक, लक्ष्मी पूजा थाल व वस्त्र, लक्ष्मी चौकी, अर्घ्यपात्र, लोटे, ऐपण सेल्फी प्वाइंट, ऐपण वॉल पेंटिंग आदि तैयार करती है।

राष्टपति ने सराहा ऐपण गर्ल को

उत्तराखण्ड दौरे पर आई राष्टपति द्रौपदी मुर्मू को एक कार्यक्रम में ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती ने ऐपण से बनी नेम प्लेट भेंट की थी और ऐपण के बारे में विस्तार से बताया था। जिसके बाद महामहिम ने लोककला के संरक्षण और संवर्धन को लेकर किए जा रहे मीनाक्षी खाती के प्रयासों को सराहा था। इसके अलावा मीनाक्षी खाती को आईआईटी कानपुर, आईआईएम काशीपुर, ऑफिसर अकादमी नैनीताल, हरिद्वार, टडस, रूम टू रीड इंडिया सहित विभिन्न संस्थानों में ऐपण पर प्रशिक्षण और व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। वहीं विभिन्न मंचों पर अनगिनत पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं।

ईजा-बैणी कार्यक्रम में ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती को सम्मानित करते मुख्यमत्री पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखण्ड सरकार भी ऐपण को दे रही है बढ़ावा

ऐपण के जरिए रोजगार सृजन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार भी ऐपण को बढ़ावा दे रही है। एक जिला दो उत्पाद के तहत नैनीताल जनपद का चयन ऐपण के लिए भी किया गया है। जिससे ऐपण के कलाकारो को फायदा मिले। उत्तराखण्ड सरकार ने रामनगर और ऋषिकेश मे आयोजित जी-२० सम्मेलन में भी ऐपण की वाल पेंटिंग्स और उत्पाद को प्रमोट किया था। यही नहीं उत्तराखण्ड आने वाले अतिथियों और दिल्ली में भी ऐपण के बनाए उत्पाद भेंट किए जाते हैं। कुल मिलाकर सरकार का भी प्रयास है कि अपनी लोककला को भी बढ़ावा मिले। ऐपण कला को जीआई टैग भी मिला है।

मीनाक्षी की ऐपण राखी

ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती वोकल फॉर लोकल मॉडल को चरितार्थ करते हुए पिछले पांच सालों से रक्षाबंधन के लिए ऐपण राखियां बना रही हैं। जिसमें ऐपण कला को खूबसूरती से उकेरा है। लोगों को ये राखियां बेहद पसंद आती हैं। ऑनलाइन के जरिए भी लोग अपनी डिमांड भेजते हैं। ऐपण गर्ल, दादी, ददा, बैणी, भुला, भैजी बौज्यू, ब्रो सहित विभिन्न नामों की ऐपण राखी तैयार करती हैं। ये दिखने में भी काफी आकर्षक लगती हैं साथ ही हमारी लोकसंस्कृति को संजोने का कार्य भी कर रही हैं। यही नहीं पर्यावरण दृष्टि से भी ये राखियां बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि इनमें कहीं पर भी प्लास्टिक या अन्य चीजों का उपयोग नहीं किया गया है। लोगों को ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती की बनाई गई ऐपण राखी बेहद पसंद आती है। बाजार में चीनी राखियों के बदले ऐपण राखी की भारी मांग है। ऐपण राखी के जरिए आज महिलाओं को घर बैठे-बैठे रोजगार मिल रहा है। विदेशों से लेकर देश के कोने-कोने से लोग ऐपण राखी मंगा रहे हैं। रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी कई महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के द्वारा भी ऐपण से बनी राखियां बनाई जा रही हैं। ऐपण गर्ल मीनाक्षी खाती कहती हैं कि मुझे खुशी है कि अब ऐपण कला घर की देहली से विश्व के फलक तक अपनी पहचान बना चुकी है और ऐपण के कलाकारों को ऐपण से स्वरोजगार भी मिल रहा है।

उत्तराखण्ड मांगे नया भू-कानून-2

हरीश रावत
पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

राजनीति में सर्वदलीय यहां तक कि सर्वपक्षीय परामर्श का अपना महत्व है। भू-कानून और इससे जुड़े हुए सवाल संवेदनशील हैं। अभी राज्य के सम्मुख आने वाले समय में और अधिक संवेदनशील मामले आने जा रहे हैं, इनमें से एकाध मामला तो सीधे-सीधे राज्य निर्माण की अवधारणा पर चोट करेगा। यूं भाजपा हमेशा संवेदनशील मुद्दों की राजनीति करती है। चाहे वह मामला जनसंख्या असंतुलन का हो या कॉमन सिविल कोड का हो, भाजपा ने हमेशा बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, बढ़ते पलायन, असहिष्णुता, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों से कन्नी काटने का प्रयास किया है। मगर नए भू-कानून की मांग संवेदनशील होने के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक व राज्य निर्माण की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। यदि हम इस मामले को और अधिक टालेंगे तो उत्तराखण्ड अपने पांव में ही कुल्हाड़ी मारेगा। हम सबका मिला-जुला प्रयास होना चाहिए कि ऐसी स्थिति आने से बचा जाए

भूमि के महत्व को वर्गीकृत करना तो देवताओं के लिए भी कठिनतर रहा है, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी', स्वर्ग से भी देवताओं ने और महापुरुषों ने गांव की माटी को महत्वपूर्ण माना है। फिर उत्तराखण्ड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है, जहां के हर गाड़ में शिवालय व हर धार में भवानी का वास हो, जहां की अदिष्टदात्री नंदा (पार्वती) हो उस धरती की मिट्टी का मूल्य यदि उसके बेटे-बेटियां नहीं समझ रहे हैं तो फिर हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। यदि हम विशुद्ध वाणिज्यिक दृष्टिकोण से भी देखें तो भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे उत्तराखण्ड के माटी के प्राकृतिक उत्पाद मूल्यवान से बहुमूल्य होते जाएंगे। मैं इस भूमि के उत्पादों के वाणिज्यिक महत्व को इंगित करने के लिए एक-दो सामान्य से उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। भांगुला (हैम्प), कंडाली (बिच्छू घास), गेठी की लकड़ी, तिमरू, थुनेर, चंद्रा, बद्री बेरी, जम्मू गंदरायणी, कीड़ा जड़ी, जखिया, चिरैता की घास के वर्तमान समय में महत्वहीन उत्पादों के भावी वाणिज्यिक महत्व को सामने लाऊं तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आपकी मिट्टी में सोना लिपटा है। हमने हैम्प जिसको भांगुला भी कहा जाता है, कंडाली, भीमल और रामबांस को भी कुछ सीमा तक, हर रेशा प्रजाति जिसमें बांस, रिंगाल आदि सम्मिलित हैं उनको अपनी गरीबी उन्मूलन का एक सशक्त माध्यम के रूप में ढूंढ़ा और अपनी राजनीति को दांव पर लगाकर कमर्शियल हैम्प के लिए कानून बनाया। अब पता चला है कि हैम्प के रेशे और औषधीय गुणों के अतिरिक्त गुणों के लिए उसके वाणिज्यिक दोहन के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। मुझे डर है एक दिन हमारा भांगुला, हमारा बिच्छू घास भी हमारा नहीं रह जाएगा। क्योंकि जितनी ऊंची चोटी होगी उसके निकट उतना ही बहु उपयोगी भांगुला, बिच्छू घास आदि पैदा होगा। क्लाइमेंट चेंज ने हमारे लिए जहां हजारों चुनौतियां खड़ी की हैं, वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों के भौगोलिक और जैविक महत्व को भी आगे बढ़ाया है। कल तक जिन क्षेत्रों में केवल फाफर और जौ आदि पैदा होते थे आज उन क्षेत्रों में आलू, सेब आदि पैदा हो रहे हैं। उसी प्रकार जिन क्षेत्रों में कल तक नारंगी, संतरे, नींबू आदि पैदा होते थे, आज उन क्षेत्रों में आम और लीची भी उत्पादित हो रही हैं। इस परिवर्तन का उच्च हिमालयी क्षेत्रों को बड़ा सार्थक लाभ भी मिल रहा है, बशर्ते हम इन क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व को परंपरागत लोगों के हाथ में ही रहने दें! यह रह पाएगा, एक बड़ी चुनौती है! जो लोग अपनी वाणिज्यिक दोहन के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, वो लोग अपनी आर्थिक लाभ के लिए यहां आ रहे हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, दोष हमारी नजर का है। गलतियां होती हैं, सुधारनी पड़ती हैं। जब २०१४ के आस- पास सोलर एनर्जी की बड़े पैमाने पर बात उठी तो हमने भगवानपुर के पास में खेलपुर, खाताखेड़ी, उधर कुछ झबरेड़ा के क्षेत्र में और कुछ अन्य क्षेत्रों में ऐसी दो-तीन सौ मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित की, इनके स्थापित होने के ६ महीने बाद जब मैं यह देखने पहुंचा कि इन परियोजनाओं में कितने लोगों को नौकरी मिल रही है तो मुझे आश्चर्य हुआ कि १०० बीघा जमीन में लगे प्रोजेक्ट में केवल ११ लोग कार्यरत थे। मैंने उसी क्षण इस आईडिया पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला लिया।

आज हम कुछ सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। वर्ष २०१८ में भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इवेंट हुआ, सवा लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने का दावा किया गया। आज अभी-अभी एक और ऐसा ही इन्वेस्टमेंट इवेंट हुआ है जिसमें साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की बात हो रही है। ज्ञातव्य है कि यह उस राज्य में हो रही है, जिस राज्य में पहले से ही देश और दुनिया के नामचीन उद्योग स्थापित हैं। हमारे राज्य में आज उद्योग बंद होने की होड़ भी लगी हुई है, बीएचईएल जैसी संस्था जिसके पास हरिद्वार में विशाल भूखंड है, वर्ष २०१४ के अपेक्षाकृत १/४ कार्य बल से काम चला रहा है। विचारणीय प्रश्न है कि भूमि उपलब्ध कहां है? हमने वर्ष २०१६ में ऊधमसिंह नगर में दो फार्मों की शीलिंग की जमीन को अधिकृत किया, काशीपुर में हिंदुस्तान पेपर मिल को दी गई जमीन को बाय बैक किया तथा गदरपुर चीनी मिल की जमीन को अधिकृत कर, इन सभी भूखंडों का प्रबंधन सिडकुल को सौंपा। आज की सरकार की नजरें इसी भूखंड पर गड़ी हुई है। हमने इन भू-खंडों के आवंटन के लिए तीन मानक निर्धारित किए थे। (१) दैवीय आपदा पीड़ित (२) भूमिहीन (३) उन उत्तराखण्डी उद्यमियों जिनमें अपने उद्यम लगाने की क्षमता विकसित हो गई हो। मैं भूमि उपयोग निर्धारित करने के सरकार के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं, प्रश्न औचित्य का है? कल यदि उत्तराखण्ड के उद्यमी उद्योग लगाने में सक्षम होंगे तो उन्हें क्या हम भूमि दे पाएंगे? दैवीय आपदा पीड़ितों को बसाने की चुनौती खड़ी होगी तो क्या हम उसका समाधान ढूंढ़ पाएंगे? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रतिक्षित हैं जिसमें मेट्रो सुविधाओं का सृजन, फ्लाई ओवर्स, रिवर फ्रंट का निर्माण, जल संचय हेतु विशाल जलाशयों का निर्माण सम्मिलित है। क्या सरकार इन क्षेत्रों में यह इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है? यदि आ रही है तो हम उसका स्वागत करना चाहेंगे। मगर जिस राज्य के पास अपने कुल क्षेत्रफल का मात्र २५ प्रतिशत हिस्सा जीवन-यापन की समस्त गतिविधियों के लिए उपलब्ध हो तो उस राज्य को कबीर दास जी के इस दोहे को याद करना चाहिए 'तेते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर।'

भूमि सुधार के क्षेत्र में हमने कई दूरगामी महत्व की पहलें प्रारंभ की, पर्वतीय चकबंदी के लिए कानून बनाया, क्लस्टर बेस खेती को बढ़ावा देने के लिए लीजिंग पॉलिसी तैयार की, वर्ग-३, वर्ग-४ जैसे कई खेती के किसान विरोधी वर्गीकरणों को समाप्त करने का फैसला लिया। दलित और कमजोर वर्ग के कब्जे की जमीनों को नियमित करने का फैसला भी लिया गया। चकबंदी को आगे बढ़ाने के लिए १४ साल बाद चकबंदी और राजस्व अमीनों आदि की भर्तियां प्रारंभ की। मेरी इच्छा थी कि लंबे समय से प्रतीक्षित जमीन के बंदोबस्त को भी प्रारंभ करें। आसन्न चुनावों के कारण हमें यह फैसला टालना पड़ा। यदि हमारे बने हुए चकबंदी कानून आपको पसंद नहीं आ रहा है या हमारे द्वारा तैयार की गई नियमावलियों में आप संशोधन करना चाहते हैं, यह आपका अधिकार क्षेत्र है। आज तो मौलिक प्रश्न यह पैदा हो गया है कि क्या हमारी जमीन बचेगी? मगर ऐसे समय में एक अपवाह फैलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि जो जमीन १० साल तक खाली रहेंगी उनको अलग से चिह्नित किया जाएगा, येलो कलर या कुछ और कलर उसके लिए मिजाज किया जा रहा है। संदेश यह दिया जा रहा है कि जो जमीनें खोदी नहीं जा रही हैं जिनका कृषि उपयोग नहीं हो रहा है या वाणिज्यिक उपयोग नहीं हो रहा है, उन जमीनों को चिह्नित किया जाएगा, जमीन मालिकों के मन में भी डर पैदा किया जा रहा है ताकि जो जमीन नहीं भी बेचने वाला है वह भी औने-पौने धाम पर अपनी भूमि को बेचने को तैयार हो जाए। कुछ बुद्धिमान अधिकारी सरकार को यह राय दे रहे हैं, सरकार राय को मानने जा रही है या नहीं, यह तो सरकार ही स्पष्ट कर सकती है, मगर उत्तराखण्ड अब बेचैन है और वह भू-कानून चाहता है। इसीलिए उसकी कल्पनाएं अब अकेले भू-कानून तक सीमित नहीं हैं, वह उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। बिना सभी चीजों पर गहराई से विचार किए वह आगे छलांग लगाना चाह रहा है। समय की पुकार है कि परेड ग्राउंड देहरादून के स्वरों को मुख्यमंत्री जी को उसका वीडियो मंगवा कर बड़े गौर से सुनना चाहिए। अधिकारियों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि भू-कानून एक सैद्धांतिक प्रश्न है? इस प्रश्न का समाधान राजनीतिक स्तर पर ही निकल जाना चाहिए। अधिकारी ऐसे निकाले गए नीतिगत निर्णय को क्रियान्वित करने का रास्ता अवश्य ढूंढ़ सकते हैं। हम वक्तीय तौर पर इस मामले को लटकाने के लिए ऐसी कमेटियां बनाकर और उलझाव ही पैदा करेंगे। पहले से ही तीन कमेटियां गठित हो चुकी हैं, वह कहां तक आगे बढ़ी हैं तथ्य सार्वजनिक नहीं हैं! एक संवेदनशील प्रश्न पर चलताऊ रवैया अपनाना उचित नहीं रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे इस विषय में सर्वदलीय यहां तक कि सर्वपक्षीय परामर्श भी आहूत कर सकते हैं। राजनीति में सर्वदलीय यहां तक कि सर्वपक्षीय परामर्श का अपना महत्व है। भू-कानून और इससे जुड़े हुए सवाल संवेदनशील हैं। अभी राज्य के सम्मुख आने वाले समय में और अधिक संवेदनशील मामले आने जा रहे हैं, इनमें से एकाध मामला तो सीधे-सीधे राज्य निर्माण की अवधारणा पर चोट करेगा। यूं भाजपा हमेशा संवेदनशील मुद्दों की राजनीति करती है। चाहे वह मामला जनसंख्या असंतुलन का हो या कॉमन सिविल कोड का हो, भाजपा ने हमेशा बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, बढ़ते पलायन, असहिष्णुता, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों से कन्नी काटने का प्रयास किया है। मगर नए भू-कानून की मांग संवेदनशील होने के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक व राज्य निर्माण की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। यदि हम इस मामले को और अधिक टालेंगे तो उत्तराखण्ड अपने पांव में ही कुल्हाड़ी मारेगा। हम सबका मिला-जुला प्रयास होना चाहिए कि ऐसी स्थिति आने से बचा जाए।

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 27 जनवरी, 2024

बर्बाद गुलिस्तां करने को...

फोटो : 'मिंट' पोर्टल से

एक बार फिर आया दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक का दवा घोटाला

आयशा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले एक साल से आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कथित शराब घोटाले का ताप झेल रहा है तो कई और घोटालों का शोर भी राजधानी में सुनाई देने लगा है। कुछ महीनों से देश की राजधानी दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की सप्लाई को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिकों में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट करवाए जाने का मामला सामने आया है। इसमें १०० करोड़ रूपए से भी अधिक के घोटाले की बात कही जा रही है। मोहल्ला क्लीनिकों को दिल्ली सरकार आम जनता को उपलब्ध कराई गई अपनी श्रेष्ठ योजनाओं में गिनती है। इस योजना के जरिए दिल्ली के नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ सुविधाओं का भारी लाभ मिल रहा है। अब लेकिन इस जनसुविधा में भारी भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद उपराज्यपाल ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई के हवाले कर दी है।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे इन मोहल्ला क्लिनिकों में हजारों मामलों में फर्जी और गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर फर्जी मरीजों का पंजीकरण किया गया और फिर निजी लैब में उनकी जांच कराने की पर्चियां काटी गई। आरोप है कि इस तरह करोड़ों रुपए की अदायगी निजी लैबोरेट्रीज को किया गया और सरकार को भारी चूना लगाया गया।

क्या है मोहल्ला क्लीनिक?

यह दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी जनउपयोगी योजना है। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने गरीबों की मदद और बड़े अस्पतालों की भीड़ कम करने के लिए मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत वर्ष २०१५ में की थी। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि लोगों को उनके दरवाजे पर ही स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। इनमें निर्धन वर्ग के लोगों को मुफ्त जांच, दवाओं और परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन मोहल्ला क्लीनिकों में २१२ तरह की जांच मुफ्त की जाती है। इसके अलावा यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि किसी मरीज को अल्ट्रासाउंड या किसी अन्य जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो डॉक्टर के लिखने पर किसी निजी लैब में वह जांच कराई जा सकती है जिसका भुगतान सरकार

द्वारा किया जाता है। ऐसे में यह मोहल्ला क्लीनिक निर्धन और अन्य वर्गों के लिए बेहद लाभकारी साबित रहे हैं। लेकिन हाल ही में सामने आए घोटाले ने इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य को भारी क्षति पहुंचाने का काम किया है।

क्या है पूरा मामला

दिल्ली सरकार ने फरवरी वर्ष २०२३ में दो निजी लैब एजिलस डाइगलोस्कि लिमिटेड और मेट्रोपोलिश हेल्थकेयर लिमिटेड के

ख्याति प्राप्त शायर शौक़ बहराइची का एक शेर वर्तमान भारत की दिशा और दशा को बड़ी साफगोई से सामने रखता है कि 'बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था हर शाख पर उल्लू बैठा है अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा।' 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मुहिम छेड़ने वाले अन्ना आंदोलन के गर्भ से उत्पन्न आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन दिनों खुद भ्रष्टाचार के आरोपों की जद् में आ चुका है। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले की तपिश अब 'आप' के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इस कथित घोटाले को केंद्र सरकार और भाजपा का षड्यंत्र करार देने वाली 'आप' लेकिन मोहल्ला क्लीनिकों में चौतरफा पसरा भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने विजिलेंस जांच में सामने आए इस घोटाले की विस्तृत जांच सीबीआई को सौंपने का एलान कर 'आप' सरकार और पार्टी को गहरी सांसत में डाल दिया है

साथ एक समझौता किया, जिसके तहत मोहल्ला क्लीनिकों में आने वाले मरीजों की पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच के लिए सहमति बनी। यानी मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों को जिन मरीजों के लिए ये टेस्ट करवाने की जरूरत लगेगी, उन्हें यहां भेजा जा सकेगा। मरीजों के टेस्ट भी मुफ्त किए जाएंगे और जो भी भुगतान होगा, वह सरकार को करना होगा।

कैसे सामने आया मामला

दिल्ली में कुल ५२६ मोहल्ला क्लिनिक हैं। बीते साल अगस्त में इनमें से सात मोहल्ला क्लीनिकों में कुछ अनियमितता पाई गई थी। यहां काम करने वाले लोग आते ही नहीं हैं और गलत तरीके से अपनी हाजिरी लगा देते हैं। खास बात ये पता चली कि स्टॉफ यहां पर पहले से ही रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर डॉक्टरों की हाजिरी लगा देते हैं। इस गोरखधंधे का खुलासा होते ही सितंबर महीने में एफआईआर दर्ज की गई और कुछ स्टाफ को हटाया भी गया। लेकिन यह सिलसिला यहां नहीं रुका। अक्टूबर में जब इन मोहल्ला क्लीनिकों के तीन महीने के टेस्ट सैंपल की जांच के लिए डाटा विजिलेंस विभाग को भेजा गया तो बड़े पैमाने पर हुए गड़बड़झाले का खुलासा हुआ। इन दोनों लैब में बीते साल जुलाई से सितंबर तक के रिकॉर्ड जुटाए गए।

विजिलेंस जांच

एजिलस डाइगलोस्कि में इन ७ मोहल्ला क्लिनिकों द्वारा जुलाई से लेकर सितंबर वर्ष २०२३ के बीच रेफर किए गए ५,२१,२२१ टेस्ट कराए गए। इसी तरह मेट्रोपोलिश हेल्थकेयर में जुलाई से सितंबर २०२३ के बीच ८५,६१६ टेस्ट करवाए गए। जांच में सामने आया है कि इन ७ मोहल्ला क्लीनिकों में फर्जी और गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया और उनकी लैब जांच कराने के लिए कहा गया। कई मोबाइल नंबर को एक से ज्यादा मरीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। ११,६५७ मरीजों का मोबाइल नंबर सिर्फ '०' लिखा गया। ८२५१ मरीजों का नंबर ही नहीं लिखा गया। ८१७ मोबाइल नंबर का इस्तेमाल १५ या उससे ज्यादा मरीजों के मामले में किया गया। ३,०९२ मरीजों के नंबर ९९९९९९९९९ दर्ज किया गया। यह मोहल्ला क्लीनिक जफर कलां, उजवा, शिकारपुर, गोपाल नगर, ढांसा, जगजीत नागर और बिहारी कॉलोनी में स्थित हैं।

डॉक्टरों की लगातार गैरमौजूदगी

जांच में यह भी पाया गया है कि इन मोहल्ला क्लीनिकों में मरीजों की मेडिकल काउंसलिंग कर, डॉक्टर की गैरमौजूदगी में अनधिकृत कर्मचारियों द्वारा दवाएं दी जाती थीं, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पिछले साल सितंबर में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके बाद पिछले साल जुलाई से सितंबर तक तीन महीनों के लिए दो प्राइवेट लैब्स द्वारा किए गए सैंपल टेस्ट की समीक्षा भी की गई। जिसमें पाया गया कि मरीजों के रजिस्ट्रेशन और बाद में उनकी प्रयोगशाला जांच के लिए फर्जी नंबर का इस्तेमाल किया गया था।

जांच में ये भी सामने आया है कि टेस्ट के लिए लेब इनफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसे आधार से लिंक करने का कोई सिस्टम ही नहीं था। विजिलेंस का ये भी कहना है कि सिर्फ सात मोहल्ला क्लीनिकों के मामले में इतनी बड़ी अनियमितताएं मिली हैं, तो बाकी का भी अगर डाटा भी जांच के लिए जाता है तो हो सकता है और बड़ा घोटाला देखने को मिले।

जांच अब सीबीआई के हवाले

इस मामले में सीबीआई को मामला भेजते हुए उपराज्यपाल ने लिखा है कि 'दिल्ली में पहले खराब क्वालिटी की दवाओं का मामला सामने आया और अब मोहल्ला क्लीनिकों में इस तरह का गोरखधंधा। इससे साफ है कि किस तरह से गरीब और मजलूम दिल्लीवासियों के अधिकार पर चोट की जा रही है। इस मामले की तह तक जाना बेहद जरूरी है।'

आम आदमी पार्टी का बयान

इस मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि उन्होंने ही २० सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ७ मोहल्ला क्लीनिक में स्टाफ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गड़बड़ी करके गलत तरीके से अटेंडेंस लगाई जा रही है, जिसके बाद उन ७ मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर, फार्मासिस्ट, मल्टी टॉस्किंग वर्कर और असिस्टेंट पर कार्रवाई करके उनको हटा दिया गया था। अब जिस डाटा की बात कही जा रही है, वो भी उन्हीं मोहल्ला क्लीनिकों का है। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है, तो

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज

अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार नीतियां बनाती है और अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है उन्हें सुचारू रूप से लागू करें और यह स्वास्थ्य विभाग के सचिव की जिम्मेदारी बनती है।'

सौरभ भारद्वाज का यह भी कहना है कि उन्होंने बीते साल २१ अप्रैल को आदेश दिए थे कि मोहल्ला क्लीनिकों के औचक निरीक्षण के लिए सीनियर डॉक्टर की फ्लाइंग स्क्वाड बनाई जाए। लेकिन स्वास्थ्य सचिव ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

आप पर हमलावर हुई भाजपा

बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में दिल्ली सरकार की नीयत पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। बकौल त्रिवेदी 'आप सरकार ने पहले मोहल्ला क्लीनिक बनाए, फिर उसका दायरा बढ़ाते हुए निजी कंपनियों को ठेका दे दिया और फर्जी बिल बना मोटा घोटाला किया। पीएम नरेंद्र मोदी इसलिए लगातार डिजिटल पर जोर देते हैं, लेकिन ये लोग उसका विरोध इसी कारण करते रहे ताकि उसकी आड़ में घोटालों को अंजाम दे सकें।'

फिर जीती चीन विरोधी पार्टी

डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की जीत का जश्न मनाते ताइवानी

दि संडे पोस्ट डेस्क

तेरह जनवरी को ताइवान में हुए आम चुनाव के नतीजे चीन के लिए सुखद नहीं रहे हैं। इस चुनाव पर विश्व भर की नजरें गड़ी थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार इस स्वशासित द्वीप पर चीन के प्रति हमदर्दी रखने वाले पैन-ब्लू गठबंधन को सत्ता मिल सकती है। चीन को यह भी उम्मीद थी कि २०१९ में गठित एक नए राजनीतिक दल ताइवान पीपुल्स पार्टी का प्रदर्शन भी ठीक-ठाक रहेगा और बीते दो चुनाव जीतने वाली चीन विरोधी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। ऐसा लेकिन हुआ नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता लाई चिंग-ते राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। २०२० से ताइवान के उपराष्ट्रपति रहे लाई चिंग-ते पैन-ग्रीन गठबंधन के नेता हैं। यह गठबंधन ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है और चीन के साथ एकीकरण का घोर विरोधी है। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व चीन के समुद्री तट से १६१ किलोमीटर दूर स्थित ताइवान १९४९ तक चीनी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। १९४९ में चीन में हुए गृह युद्ध के बाद वहां कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया था। इस गृह युद्ध से पहले चीन की सत्ता पर राष्ट्रवादी पार्टी कोमिंतांग की सत्ता थी। इस गृह युद्ध जिसे चीन की लाल क्रांति कह पुकारा जाता है, में हुई हार के बाद कोमिंतांग के नेताओं ने चीन छोड़ ताइवान द्वीप समूह में शरण ले ली थी। कोमिंतांग ने तभी से ताइवान को चीन से अलग एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। चीन इसे नहीं स्वीकारता है और ताइवान को चीन का अभिन्न अंग मानता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार कहते रहे हैं कि ताइवान को चीन के साथ एकीकृत कराया जाना तय है। दूसरी तरफ पश्चिमी देश चीन के इस मंसूबे को रोकने की नीयत से ताइवान को सैन्य ताकत बनाने का काम करते रहे हैं। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का ताइवान पर कब्जा पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन को ताकतवर बनाने और इस इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे चीनी सेना के निशाने में लाने का काम करेगा। यही कारण है कि अमेरिका एवं उसके सहयोगी देश ताइवान में मौजूद चीन विरोधी राजनीतिक दलों को समर्थन देते आए हैं।

निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते

चीन विरोधी हैं नए राष्ट्रपति

ताइवान में बीते आठ वर्षों से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की नेता साई इंग-वेन राष्ट्रपति हैं। वे ताइवान की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं। ताइवानी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति केवल दो टर्म के लिए ही चुना जा सकता है। २०१६ में राष्ट्रपति बनी साई इंग-वेन २०२० में दोबारा चुनाव जीती थीं। संवैधानिक बाध्यता के चलते वे तीसरा चुनाव नहीं लड़ी और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति लाई चिंग-ते को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाया। पेशे से डॉक्टर रहे लाई भी घोर चीन विरोधी नेता हैं। उनकी जीत के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब ताइवान अमेरिका के साथ अपने संबंधों को ज्यादा मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ेगा। चीन की नजरों में लाई वर्तमान राष्ट्रपति साई इंग-वेन से कहीं ज्यादा अलगाववादी और अमेरिकी समर्थक हैं।

बड़ी सैन्य ताकत बन उभर रहा है ताइवान

चीन के लिए ताइवान द्वारा लगातार अपनी सैन्य ताकत का विस्तार करना एक बड़ी समस्या बन चुका है। हालांकि चीन के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है और ताइवान हर दृष्टि से चीन की सैन्य क्षमता के आगे कमजोर है लेकिन अमेरिका द्वारा उसे भारी तादात में हथियार और सैनिक विमान उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो चीन के लिए चिंता का बड़ा मुद्दा बन चुका है। गत् वर्ष जुलाई में ही अमेरिका ने ताइवान को सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग ३५ करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए जाने की घोषणा कर चीन की खासी नाराजगी मोल ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन लगातार कहते आए हैं कि यदि चीन ताइवान पर कब्जा करने की नीयत से सैन्य हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा।

बड़ी आर्थिक शक्ति है ताइवान

लगभग दो करोड़ की जनसंख्या वाला ताइवान विश्व की बड़ी आर्थिक ताकत वाला देश २०वीं शताब्दी के मध्य में उभरा था। उसकी इस आर्थिक तरक्की को 'ताइवान मिरेकल' (ताइवान का जादू) कह पुकारा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दृष्टि से यह छोटा सा देश विश्व की २१वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति वाला देश है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है। सेमी कंडक्टर उद्योग में ताइवान की कंपनियों की वैश्विक हिस्सेदारी लगभग आधी है। यहां की एक कंपनी 'ताइवान सेमी कंडक्टर माइक्रो इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन' विश्व की सबसे बड़ी सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनी है जो इंटेल और सैमसंग से कई गुना बड़ी है। अमेरिका द्वारा ताइवान पर चीन के कब्जे को हर कीमत पर रोकने की मंशा के पीछे ताइवानी टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा कारण है। पश्चिमी देशों को भय है कि यदि चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो विश्व के एक अति महत्वपूर्ण उद्योग पर उसका एकतरफा राज हो जाएगा।

संकट में नेबरहुड फर्स्ट नीति

दि संडे पोस्ट संवाददाता

पड़ोसी मुल्क मालदीव के संग भारत के रिश्ते हालिया समय में बेहद तनावपूर्ण हो चले हैं। हालांकि यह एशिया का सबसे छोटा देश है लेकिन सामरिक दृष्टि से यह भारत के लिए खासा महत्व रखता है। भारतीय विदेश नीति हमेशा से ही मालदीव के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की रही है। १९८८ में जब यहां के तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम की सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश कुछ विद्रोही सैनिकों ने की थी तो भारत अकेला ऐसा देश था जिसने गयूम के अनुरोध पर तत्काल भारतीय सेना भेज इस विद्रोह को असफल कर दिया था। तभी से भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी मालदीव में तैनात रहती आई है। मुख्यतः इस टुकड़ी का काम मालदीव के आस-पास के समुद्री इलाकों की निगरानी करना और इस द्वीप समूह में आपदा के समय में राहत उपलब्ध करानी है। वर्तमान में लगभग ८८ भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात हैं। गत् वर्ष सितंबर में मालदीव में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। तब तक भारत के मालदीव संग संबंध खासे प्रगाढ़ थे। तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह भारत समर्थक थे और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान चीन के बजाए भारत को तवज्जो दी थी। सितंबर, २०२३ में सोलेह राष्ट्रपति चुनाव हार गए और चीन समर्थक मोहम्मद मुइज्जू देश के नए राष्ट्रपति बने।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू

चीन के कट्टर समर्थक हैं मुइज्जू

मोहम्मद मुइज्जू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता हैं जो चीन समर्थक पार्टी है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मुइज्जू ने 'इंडिया आउट' का नारा दिया था। उन्होंने राष्ट्रवाद की भावनाओं को सुलगाते हुए कहा था कि वह मालदीव की धरती से विदेशी सेना को बाहर निकालने का काम करेंगे। दूसरी तरह तत्कालीन राष्ट्रपति सोलेह ने 'इंडिया फर्स्ट' के नारे तले चुनाव लड़ा था। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ही मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से तत्काल अपने सैनिक वापस बुलाने की बात कह डाली थी। दिसंबर, २०२३ में उन्होंने २०१९ में भारत संग हुए 'हाइड्रोग्राफिक सर्वे' समझौते को रद्द कर द्विपक्षीय संबंधों को निम्नतम स्तर तक पहुंचाने का काम कर डाला। इस समझौते के अंतर्गत भारत और मालदीव मिलकर मालदीव के जल क्षेत्र तथा सामुद्रिक लहरों का अध्ययन करते थे। नए राष्ट्रपति ने दशकों से चली आ रही एक और परंपरा को तोड़ते हुए पद संभालने के बाद अपनी पहली यात्रा भारत की नहीं की। वे पहले तुर्की गए और उसके बाद उन्होंने चीन की यात्रा कर यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे भारत के बजाए चीन संग नजदीकियां बढ़ाने के पक्षधर हैं।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मुइज्जू का चीन दौरा

मालदीव के राष्ट्रपति को चीन ने हाथों हाथ लिया है। उनकी इस यात्रा के दौरान २० समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चीन से वापस लौटते ही मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को १५ मार्च तक मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम दे डाला। राष्ट्रपति का कहना है कि उनके देश में विदेशी सैनिकों का होना, मुल्क की संप्रभुता के खिलाफ है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि मुइज्जू सरकार चीन के साथ रिश्तों को इसलिए भी ज्यादा प्रगाढ़ बनाना चाहती है क्योंकि मालदीव पर चीन का भारी कर्ज है जिसे चुकाना वर्तमान में संभव नहीं है।

कुल मिलाकर मालदीव में नए राष्ट्रपति की ताजपोशी के बाद से ही भारत संग मालदीव के संबंधों में भारी तनाव आने लगा है जो आने वाले समय में और गहरा सकता है।

टीम इंडिया में हुई पोस्टर वॉर की एंट्री

गुजरात टाइटंस द्वारा जारी किया गया पोस्टर

आईपीएल 2024 के लिए जैसे ही मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा से टीम की कमान छीनकर हार्दिक को दी है तभी से रोहित और टीम मैनेजमेंट के बीच मनमुटाव की बातें कही जा रहीं हैं। हालांकि इस पर दोनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जब से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए टीम इंडिया ऐलान हुआ है तब से इस बात को और हवा मिलने लगी है। यहां तक कि अब मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस दोनों फ्रेंचाइजियों में पोस्टर वॉर की भी एंट्री हो गई है

मुंबई इंडियंस द्वारा जारी पोस्टर

जीवन सिंह टनवाल

हमारे देश में क्रिकेट एक ऐसा खेल बन गया है जिसे खेल प्रेमी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इनका यह प्रेम तब और बढ़ गया जब वर्ष २००७ में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत हुई। यह लीग खेलों में सबसे महंगी लीग के साथ ही अब दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग भी बन गई है। इस लीग से कई ऐसे खिलाड़ी उभरकर आए हैं जो अब देश का नाम रोशन कर रहे हैं।

इस बीच खबर है कि आईपीएल का १७वां संस्करण २२ मार्च से खेला जा सकता है। ऐसे में इसकी तैयारी में तेजी आ गई है। इसी के तहत पिछले महीने आईपीएल नीलामी २०२४ के लिए खिलाड़ियों की बोली लग चुकी है, जहां ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और गेंदबाज पर जमकर पैसा बरसा। ये खिलाड़ी इतने महंगे बिके कि आईपीएल इतिहास के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। दूसरी ओर इस आईपीएल से पहले सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के उस फैसले की हो रही है जिसमें पांच बार आईपीएल चौंपियन मुंबई इंडियंस की कप्तानी से रोहित शर्मा को हटा दिया गया और हार्दिक पांड्या को बिना देर किए कप्तान भी घोषित कर दिया गया। लेकिन हार्दिक पांड्या पिछले साल के अंत में खेले गए एक दिवसीय आईसीसी वर्ल्ड कप से ही चोटिल चल रहे हैं।

कयास लगाए जा रहे थे कि वे वर्तमान में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की टी-२० सीरीज टीम में वापसी कर सकते हैं, मगर उन्हें टीम में जगह नहीं मिलने से चोटिल माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान कौन होगा? क्या रोहित शर्मा को फिर से टीम की कमान दी जाएगी? क्या वे इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे? या फिर किसी अन्य खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी जाएगी? इस बीच जब से इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए टीम इंडिया ऐलान हुआ है तब से कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस दोनों फ्रेंचाइजियों में पोस्टर वॉर की एंट्री भी हो गई है।

मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स से भारतीय टीम को साझा किया तो पोस्टर से रोहित की तस्वीर ही गायब कर दी। पोस्टर में केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर की तस्वीर साझा की गई। ऐसा करते ही एक बार फिर सोशल मीडिया पर रोहित के फैंस सक्रिय हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस द्वारा भारतीय टीम के कप्तान रोहित की तस्वीर पोस्टर पर नहीं लगाना बहुत कुछ कह गया है। भले ही दोनों में से कोई भी खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है लेकिन रोहित और मुंबई इंडियंस के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की पुष्टि होती दिख रही है।

इसका अंदाजा हाल ही में गुजरात टाइटंस के पोस्टर से भी समझा जा सकता है। जिस तरह गुजरात ने अपने पोस्ट में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की तस्वीर लगाई इससे भी यही समझ में आया कि गुजरात की टीम रोहित को रिझाने में जुटी है। यहां तक कहा जा रहा है कि आईपीएल की ट्रेड विंडो नीलामी के बाद से खुली है अगर विवाद बढ़ा तो रोहित के मुंबई से गुजरात जाना महज औपचारिकता रह जाएगी।

खेल विश्लेषकों का कहना है कि एक कहावत है, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है। वर्तमान में यह कहावत मुंबई इंडियंस पर सटीक साबित होती दिख रही है। हार्दिक पांड्या के गुजरात से मुंबई में वापसी के बाद से पांच बार की चैंपियन मुंबई के टीम में जाने से हलचल स्वाभाविक है। क्योंकि हार्दिक की मुंबई इंडियंस में वापसी होते ही रोहित शर्मा की कप्तानी से छुट्टी हो गई।

इसके बाद मुंबई इंडियंस की मालकिन को रोहित के फैंस के कहर का सामना करना पड़ा। यहां तक कि लाखों की संख्या में रोहित के फैंस ने मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया। इसका पहला कारण यह कि रोहित को अचानक कप्तानी से हटाया गया जो हर किसी को नागवार गुजरा। सोशल मीडिया में रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के बीच दरार की बातें आने लगीं हैं। हालांकि रोहित शर्मा और मुंबई टीम मैनेजमेंट ने इस बारे में खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन इस विवाद को हवा इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टेस्ट सीरीज के पहले दो मैचों के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद फिर से मिलने लगी है।

जानकारों का कहना है कि मुंबई इंडियंस में अगर हार्दिक पांड्या चोट के चलते नहीं खेले तो फिर अगला कप्तान कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में टीम का अगला कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी बनाया जा सकता है। जिस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल २०२३ के दौरान भी रोहित शर्मा की गैर-मौजूदगी में कई बार कप्तानी की थी तो वहीं हाल में ऑस्ट्रेलिया सीरीज और साउथ अफ्रीका दौरे पर उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए भी देखा गया है। इसलिए अगर हार्दिक पांड्या स्वस्थ नहीं हो पाते हैं तो मुंबई इंडियंस की कमान सूर्य कुमार यादव को दी जा सकती है।

गौरतलब है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल २०२४) की शुरुआत इस बार मार्च के मध्य में हो सकती है। क्योंकि देश में आम चुनाव होना है और १ जून से वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में टी-२० वर्ल्ड कप खेला जाना है। अगर बात करें आईपीएल २०२३ की उपविजेता टीम की तो इस बार २०२४ में गुजरात टाइटंस की कप्तानी युवा बल्लेबाज शुभमन गिल करेंगे। क्योंकि गुजरात टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या अब मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान बन गए हैं। वहीं चैंपियन मुंबई इंडियंस ने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है। रोहित की ही अगुआई में मुंबई के पांचों खिताब जीते हैं, लेकिन अब टीम हार्दिक की कप्तानी में खेलेगी। हालांकि, इसके बाद मुंबई के कुछ खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर बिना किसी का नाम लिए इशारों-इशारों में नाराजगी जाहिर की थी। रोहित के चेहरे पर भी नाराजगी दिखी थी। नाराजगी का आलम यह था कि मुंबई के किसी खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर हार्दिक का स्वागत नहीं किया था।

अब इस मामले पर मुंबई इंडियंस और भारत के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का बयान सामने आया है। रोहित और हार्दिक के बीच किसी संभावित टकराव के बारे में इनका कहना है कि जब खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। अगर उनके बीच कोई मुद्दा तो उन्हें निश्चित रूप से बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए।

जब हार्दिक मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे तो रोहित उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रहते थे। खासकर गेंदबाजी के मामले में और वह हार्दिक के वर्कलोड का काफी ध्यान रखते थे। हार्दिक डेथ ओवरों में बल्ले से हमेशा अच्छे रहे हैं। गुजरात के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वह एक विशेषज्ञ बल्लेबाजी की तरह खेले।

गुजरात टाइटंस के लिए २०२२ से २०२३ तक ३१ मैचों में पांड्या ने ३७.८६ के औसत और १३३ से अधिक के स्ट्राइक रेट से ८३३ रन बनाए। इनमें छह अर्धशतक और नाबाद ८७ का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा था। उन्होंने टीम के लिए ११ विकेट भी लिए, जिसमें १७ रन देकर तीन विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही। हार्दिक ने २०१५-२०२१ तक मुंबई इंडियंस के लिए ९२ मैच भी खेले हैं, जिसमें १५३ से अधिक के स्ट्राइक रेट और २७.३३ की औसत से १ हजार ४७६ रन बनाए। इनमें चार अर्धशतक शामिल हैं और ९१ रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। उन्होंने टीम के लिए ४२ विकेट भी लिए, जिसमें २० रन देकर ३ विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही। हार्दिक ने पांच आईपीएल ट्राफियां जीती हैं। चार मुंबई इंडियंस (२०१५, २०१७, २०१९, २०२०) के साथ और एक गुजरात टाइटंस (२०२२) के साथ।

अपने ही जाल में फंसी नीता अंबानी!

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल २०२४ से पहले कई बड़े-बड़े फैसले लिए हैं जिसकी वजह से मुंबई के फैंस नाराज चल रहे हैं। जिससे मुंबई को उसके ही एक फैसले से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर अपनी टीम का कप्तान बना दिया। इस ट्रेड के लिए मुंबई इंडियंस ने गुजरात को १०० करोड़ की मोटी रकम दी वहीं १५ करोड़ की फीस हार्दिक पांड्या की है। इस हिसाब से हार्दिक पांड्या के लिए मुंबई इंडियंस को ११५ करोड़ रुपए खर्च करने पड़े लेकिन अगर हार्दिक चोट से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं तो मुंबई का ये पैसा बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है।

इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम

दि संडे पोस्ट, देहरादून, 27 जनवरी, 2024

आपके जाने से 'मां' बहुत जोर से याद आई

शोभा अक्षर

हिंदुस्तान की हिन्दुस्तानियत के लिए मुनव्वर सा'ब का जाना जैसे मछलियों के लिए एकाएक समुंदर से पानी का सूख जाना। यह नुकसान अदब और अवाम, दोनों के हिस्से का साझा नुकसान है। मुनव्वर राना शा'इर क्या थे, जैसे एक सदी थे। जिनकी आंखों ने इस जहां की अनगिनत त्रासदियों को देखा, जिसमें उनके अपने लोग भी बंटवारे के बाद एक-एक कर उस पार चले गए, कभी फिर वापस न आने के लिए। जिन्होंने उभरती और मरती कौमों की बादशाहियां देखीं। सियासत की आंख से आंख मिलाकर बात करने वाला वह शा'इर, अपने घर की औरतों की सोहबत में बना एक अदबी इंसान। उन्होंने लिखा भी है, 'दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के जिद, इतनी कि खुद ताज उठा कर नहीं पहना।' उनके इस शे'र से जो पहला वाक्या यहां दर्ज करने का मन हो रहा है वह यह कि वर्ष २०१४ में उन्हें 'शाहदाबा' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसी के अगले वर्ष यानी २०१५ में उन्होंने दादरी में अखलाक, उससे पहले सीपीआई नेता गोविंद पनसारे और लेखक कलबुर्गी की हत्या के प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। यह एक शा'इर की खुद्दारी ही थी वरना सियासत के दरबार में कई दिग्गज अपनी शख्सियत खो बैठते हैं।

अपना सम्मान चिह्न और एक लाख रुपए की राशि वापस करते हुए उन्होंने कहा था 'मैं रायबरेली का रहने वाला हूं। सत्ता हमारी शहर की नालियों में बहकर दिल्ली पहुंचती थी। जब दादरी की घटना हुई, मैं दोहा में था। मैंने फेसबुक पर इसे आतंकी घटना कहा तो मुझ पर चारों ओर से हमले होने लगे। इस देश में बिजली के तार नहीं जोड़े जा पाते, लेकिन मुसलमानों के तार न जाने किससे-किससे जोड़ दिए जाते हैं।'

यह एक टीस थी उस गहरे खाई की जो सियासी लोगों की वजह से थी, जिसे उन्होंने अपने हिंदी-उर्दू शायरी अदब से भरसक पाटने की कोशिश की। लगातार लिखते रहे, बोलते रहे, अपने अंतिम दिनों तक मंचों से सरे-आम रोते रहे जैसे कोई बच्चा रोता है। उनकी उंगलियां हमेशा सच की ओर इशारा करती रहीं। उंगलियां ऐसा करती भी क्यों न, उन्होंने अपने बुजुर्गों की उल्टी जूतियां जो खूब सीधी की थीं। एक साक्षात्कार में वे बताते हैं कि जब उन्होंने साहित्य अकादमी लौटाया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोगों के हवाले से उनके पास कई मर्तबा मिलने का बुलावा आया। मगर हर बार उन्होंने मना किया। मगर शा'इर वो भी एहसासों को तरजीह देने वाला शख्स, एक बार पिघल गया।

हुआ यूं कि जब मुनव्वर राना सा'ब की मां का इंतकाल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक पत्र लिखा और उनके मां के जाने पर दुःख व्यक्त किया। इस शा'इर पर इस बार असर होना ही था, उन्हें महसूस हुआ कि अब तो यह कर्ज उतारना पड़ेगा। इस तरह वे आखिर एक मर्तबा बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए। मां के जिक्र से उनके बचपन का एक वाक्या जो वे अक्सर याद कर रोने लगते थे, वह यह कि मुनव्वर अली (मुनव्वर राना) के पिता अनवर अली जब ट्रक चलाते थे और बहुत दिनों तक उन्हें बाहर रहना पड़ता था तो मुफलिसी के उन

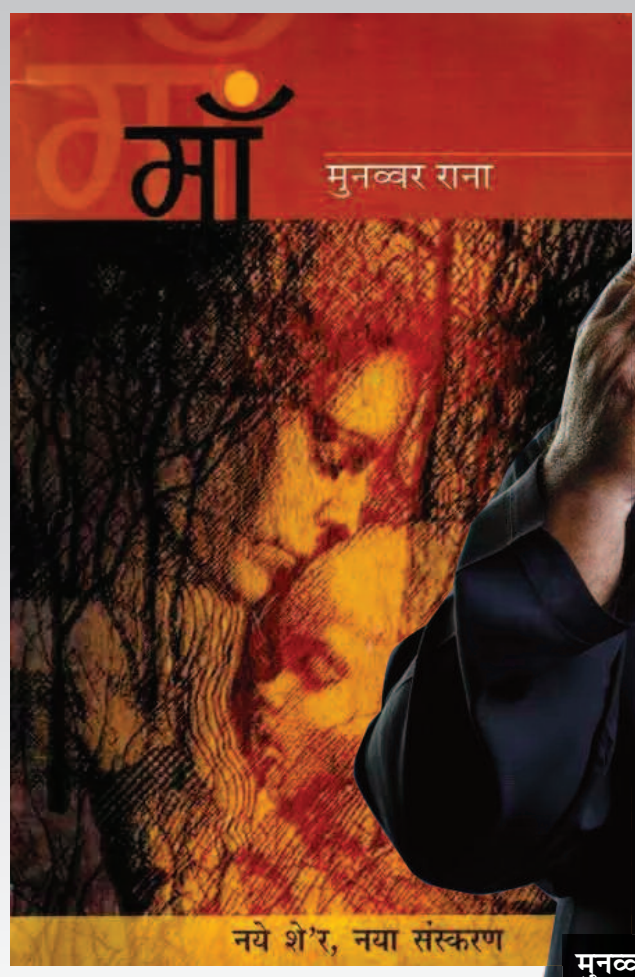

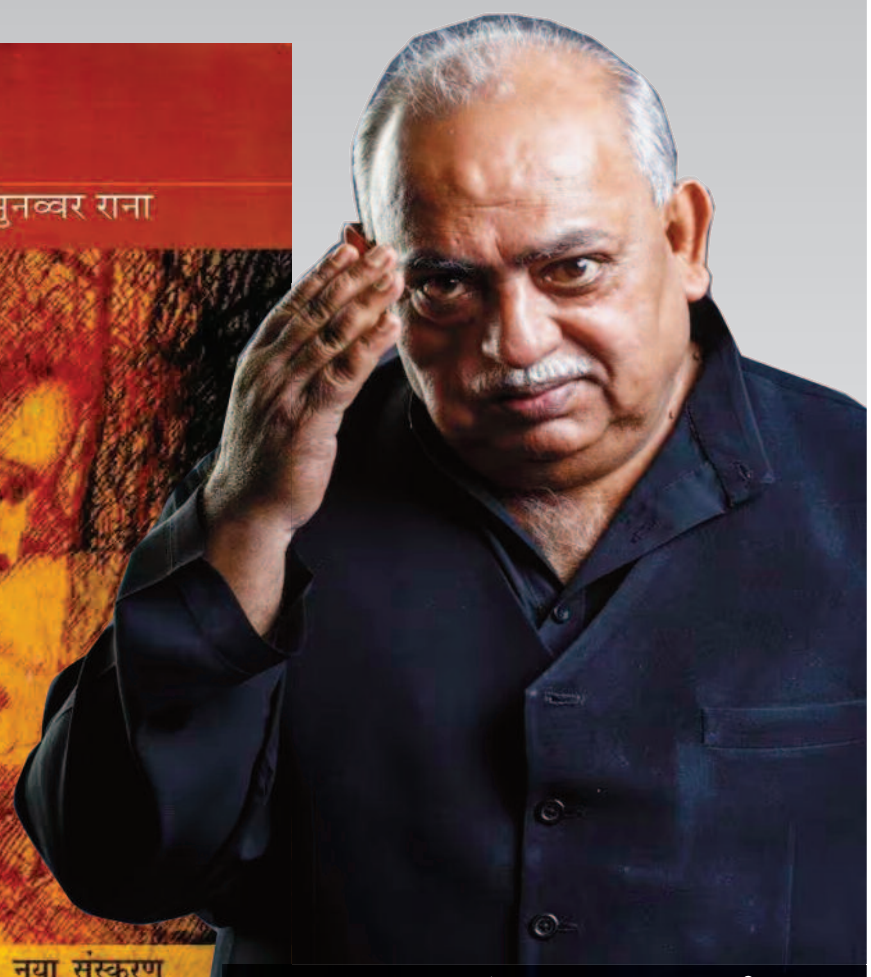

मुनव्वर राना : (26 नवंबर 1952 - 14 जनवरी 2024)

दिनों में जब कई-कई दिन घर पर चूल्हा नहीं जलता था तो इनकी मां इन्हें इनकी खाला के साथ उनके घर भेज देती थीं, ताकि बच्चों को वहां खाना तो मिल जाएगा, भूखे तो नहीं सोएंगे।

खाला के घर बच्चे जाते, जब तक घर के हालात ठीक नहीं होते तब तक रुकते और फिर वापस आ जाते। खाला के घर के ठीक सामने एक कुआं था और उन दिनों मुनव्वर को रात में चलने की बीमारी थी। इधर मां को इस बात का डर सताता कि अगर नींद में वह चलते-चलते किवाड़ खोलकर आगे चलता गया तो कुएं में गिर जाएगा, डूब गया तो! इसी डर से मुनव्वर की मां रातभर सोती नहीं, बेचैनी में घर के पास गांव में एक कुएं के पास जाकर बैठ जातीं और रोती रहतीं, मुनव्वर के सलामती की दुआएं करतीं। उन्हें लगता पानी का पानी से रिश्ता होता है, इस कुएं के पानी से इल्तिजा करतीं कि अगर मुनव्वर वहां उस कुएं में गिर गया तो उस पानी तक मेरी बात पहुंचा दो कि वो मेरे बेटे को डुबाए नहीं। ऐसी मां पर मुनव्वर ने अपनी कलम से जो लिखा, वह भी कम ही लगता है।

मां पर उनकी सबसे मशहूर नज़्म है,

किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकां आई
मैं घर में सब से छोटा था मिरे हिस्से में मां आई

यहां से जाने वाला लौटकर कोई नहीं आया
मैं रोता रह गया लेकिन न वापस जा के मां आई

राना सा'ब कहते थे कि जब दूसरे शा'इर अपनी प्रेमिकाओं को, खुदा को महबूब मानकर शायरी लिख सकते हैं तो मैं अपनी मां को महबूब मानकर शायरी क्यों नहीं कर सकता। इस बात से उनके स्कूली दिनों का एक वाक्या याद आता है, तब वे और उनका परिवार कलकत्ता में ही रहता था। लड़कपन के दिनों से ही मुनव्वर उर्दू गजलें लिखने लगे थे। तब उनके एक बंगाली दोस्त ने कहा था कि 'जब तुम्हारी उर्दू कोठों की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तब हमारी बांग्ला भाषा और उसका साहित्य अंग्रेजों से पंजे लड़ा रहा था।' यही वो बात थी जो उनके सीने में घाव कर गई थी और फिर मुनव्वर राना ने इसमें नया करने का सोचा होगा, आगे हम वाकिफ हैं कि उर्दू शायरी को जाहिर तौर पर उन्होंने अपने प्रयोगों से ऊंचा मकाम दिया। जब और शा'इर अपनी कलम से माशूका के होंठों, आंखों, उसके दुपट्टे तक ही सीमित थे तब मुनव्वर सा'ब की नज़्मों में हिंदुस्तानी रूह की तासीर तारी होती है, बंटवारें के दर्द को अपनी स्याही में उतारा। एकता, अमन, गंगा-जमुनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए अपनी कलम को मशाल बना दिया।

अपनी मां के साथ मुनव्वर राना

उन्होंने मां पर खूब लिखा। इसके साथ ही घर पर लिखा, पिता पर, बहन पर, दादी-नानी पर लिखा, भाइयों पर लिखा। मैंने ऊपर लिखा भी कि अपने घर की औरतों की सोहबत से बना एक मुकम्मल इंसान। मुकम्मल इंसान इसलिए क्योंकि उसे अपनी मां, बहनों और बेटियों का दर्द महसूस करना आता था, उसे रोना आता था। तथाकथित मर्दवादी अहम से कोसों दूर, अपने पिता की तरह। उन्होंने एक जगह जिक्र किया है कि सन् ५७-५८ की बात है, फूफियों के इश्क में उनकी दादी पाकिस्तान जाना चाहती थीं, बहुत जिद करने पर उनके पिता ने दादी को पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पर एक जानने वाले के साथ बैठा दिया। मगर जब तक ट्रेन ओझल नहीं हो गई, तब तक वह उसके पीछे भागते रहे, चिल्लाते रहे कि 'कि अम्मा एक बार रुक जा, अबही न जा। उतर आवा अम्मा, उतर आवा... ना जा अम्मा...' प्लेटफार्म पर पैर लड़खड़ाने से कई बार गिरते, फिर उठते। फिर वही पुकार...। छोटे से मुनव्वर ने यह सब देखा था। महसूसा था, अपने पिता के भीतर के बेटे को। उन्हें बाद में भी याद आता रहता था अपनी दादी का वह कहा जो उन्होंने उनकी मां से कहा था कि 'मुन्ना को कभी मारना मत, इसे मारोगी तो समझ लेना तुम मुझे मारोगी!' दादी के पाकिस्तान चले जाने के बाद जब भी इनकी मां इन्हें मारने दौड़ती तो उन्हें अपनी सास का कहा याद आता, इस तरह उन्होंने अपने अंतिम सांस लेने तक कभी भी अपने बेटे पर हाथ नहीं उठाया था।

खैर, जो लोग एक खास राजनीतिक विचारधारा के चलते मुनव्वर सा'ब को मजहबी खेमों में बांटते हैं उन्हें अंदाजा नहीं कि यह शख्स ताउम्र सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा रहा। उनकी रचनाओं का अधिकांश हिस्सा सिर्फ एक आवाज उठाता है, प्रतिरोध की आवाज। उन्हीं के शे'र का एक हिस्सा है कि 'मैं दूर तक फैले अपने दायरे को खुद समेट भी सकता हूं।' और आखिर, एक आजाद कलम के मालिक मुनव्वर राना सा'ब ने खुद को समेट लिया। मुझे इस शख्स के जिंदगी का कोई वरक, कोई हर्फ मैला नहीं दिखाई देता।

(लेखिका लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका 'हंस' से जुड़ी हैं एवं स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

संजय और उनकी मां का दौर

अपूर्व
editor@thesundaypost.in

जेपी की रैली में गूंजे नारों की धमक इंदिरा तक उनकी खुफिया एजेंसियां लगातार पहुंचा रही थी। बगैर वक्त गंवाए प्रधानमंत्री आपातकाल लगाने का निश्चय कर राष्ट्रपति से सलाह-मशिवरा करने राष्ट्रपति भवन जा पहुंची। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा की कृपा चलते ही देश के सर्वोच्च पद पर पदासीन हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मात्र इतना जानना चाहा था कि क्या उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुला सहमति प्राप्त कर ली है? प्रधानमंत्री का जवाब था कि हालात बेहद नाजुक हैं और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए जाने तक का समय नहीं बचा है। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि आपातकाल की घोषणा किए जाने पश्चात् वे मंत्रिमंडल से इस बाबत अनुमोदन प्राप्त कर लेंगी। फखरुद्दीन अली अहमद ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। प्रधानमंत्री दरअसल अपने मंत्री मंडलीय सदस्यों तक को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगी थीं। विशेषकर दलित नेता और सरकार में रक्षामंत्री जगजीवन राम को वे पार्टी भीतर अपना प्रतिद्वंद्वी मानती थीं। उन्हें आशंका थी कि आपातकाल लगाए जाने की भनक यदि जगजीवन राम को लग गई तो वे मंत्रिमंडल की बैठक में इसका विरोध कर सकते हैं। एक कमजोर हड्डी वाले राष्ट्रपति से कुछ भी करा लेने की अपनी क्षमता से प्रधानमंत्री परिचित थी। उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की उद्घोषणा बगैर मंत्रिमंडल की सहमति प्राप्त किए, स्वीकृत करा २५ जून की मध्य रात्रि आजाद भारत के स्वर्णिम लोकतांत्रिक इतिहास को बदलने और कुचलने का काम कर दिखाया। राष्ट्रपति से उद्घोषणा पर हस्ताक्षर कराने के साथ ही इंदिरा और उनके छोटे पुत्र संजय ने दमन चक्र धारण करने में देर नहीं लगाई थी। २५ जून १९७५ की रात (अथवा २६ जून की सुबह) से ही विपक्षी दलों के नेताओं की धर-पकड़ शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री आवास पर तत्कालीन गृह राज्यमंत्री ओम मेहता और दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल बिशन चंद पूरी रात मौजूद रह संजय गांधी के इशारे पर लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने में जुटे रहे थे। रात तीन बजे जब सिद्धार्थ शंकर रे प्रधानमंत्री आवास से बाहर जा रहे थे तो उन्हें ओम मेहता ने जानकारी दी कि दिल्ली के सभी समाचार पत्रों के दफ्तर और प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काटी जा रही है और सभी अदालतों को भी कल बंद रखने के आदेश दिए जा रहे हैं। शंकर यह सुन हतप्रभ हो उठे। तत्काल इस 'बकवास' को रोकने की बात कह वे दोबारा प्रधानमंत्री से मिले। इंदिरा गांधी यह सुन हैरान हो उठीं। सिद्धार्थ शंकर को थोड़ा इंतजार करने के लिए कह वे संभवतः संजय गांधी से बात करने घर भीतर चली गईं। शंकर अनुसार लगभग पंद्रह मिनट बाद जब वे बाहर आईं तो उनकी आंखें लाल थीं। वे निश्चित ही रोई थीं। उन्होंने रे से कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। न तो अखबार के दफ्तरों की बिजली काटी जाएगी और न ही अदालतें बंद रहेंगी। इस बीच संजय गांधी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल को फोन कर इस घटनाक्रम की जानकारी दी तो बंसीलाल ने उन्हें कहा-'इस आदमी (सिद्धार्थ शंकर रे) को निकाल बाहर कीजिए... यह सारा खेल बिगाड़ रहा है... यह खुद को बड़ा कानूनी विशेषज्ञ समझता है, हकीकत में इसे कुछ आता-जाता नहीं है।' प्रधानमंत्री के कहे का लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। सरकार समर्थक अंग्रेजी दैनिक 'द हिंदुस्तान टाइम्स' और 'स्टेट्मैन' को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण अखबारों के दफ्तरों की बिजली २५ जून की रात काट दी गई।

विपक्षी दल के नेताओं की गिरफ्तारी का दौर तत्काल ही शुरू हो गया। २५ जून की रात तीन बजे दिल्ली स्थित 'गांधी शांति प्रतिष्ठान' के एक कमरे में रुके जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का समाचार सुन तत्काल जेपी के पास पहुंचे चंद्रशेखर को भी हिरासत में ले लिया गया। मोरारजी देसाई, राजनारायण भी इसी रात गिरफ्तार कर लिए गए। २६ जून की सुबह साढ़े सात बजे बैंगलौर (अब बेंगलुरु) के विधायक हॉस्टल में रुके जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी हिरासत में ले लिए गए। २६ जून की सुबह ६ बजे इंदिरा मंत्रिमंडल की आपात बैठक प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई। इस बैठक में मौजूद मंत्रियों को पता तक नहीं था कि आपातकाल लागू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य में इस बात की जानकारी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से साझा की। बगैर किसी प्रतिरोध मंत्रिमंडल ने आपातकाल पर अपनी मोहर लगाने में देर नहीं लगाई थी। संजय गांधी इस दौरान प्रधानमंत्री आवास के सर्वेसर्वा बन चुके थे। उनके निर्देश न मानने का परिणाम तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री इन्द्र कुमार गुजराल पर खासा भारी पड़ा था। आपातकाल लगने के दूसरे ही दिन उनके स्थान पर संजय गांधी के विश्वस्त विद्याचरण शुक्ल को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बना दिया गया था। प्रेस (मीडिया) पर सख्त पाबंदियों का दौर विद्याचरण की निगरानी पर बड़े पैमाने में शुरू कर दिया गया। हरेक समाचार को प्रकाशित करने से पहले सरकार से स्वीकृत कराए जाने का आदेश जारी कर पूर्ण सेंसरशिप लागू कर दी गई। सेंसरशिप का विरोध करते हुए अंग्रेजी दैनिक 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने २८ जून से अपना संपादकीय पृष्ठ पूरी तरह काला प्रकाशित किया। इसी समूह के आर्थिक अखबार 'फाइनेंसियल एक्सप्रेस' ने रवींद्रनाथ ठाकुर की कविता 'जहां चित्त भय से शून्य हों (Where mind is tree fo fear) प्रकाशित कर अपना प्रतिरोध दर्ज कराया था। रवींद्रनाथ की बांग्ला में लिखी इस कविता का अनुवाद हिंदी में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने कुछ यूं किया है-

जहां चित्त भय से शून्य हो
जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सकें
जहां ज्ञान मुक्त हो
जहां दिन रात विशाल वसुधा को खण्डों में विभाजित कर छोटे और छोटे आंगन न बनाए जाते हों
जहां हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो
जहां हर दिशा में कर्म की अजस्र नदी के स्रोत फूटते हों और निरंतर अबाधित बहते हों
जहां विचारों की सरिता तुच्छ आचारों की मरु भूमि में न खोती हो
जहां पुरुषार्थ सौ-सौ टुकड़ों में बंटा हुआ न हो
जहां पर सभी कर्म, भावनाएं, आनंदानुभुतियां तुम्हारे अनुगत हो
हे पिता, अपने हाथों से निर्दयतापूर्ण प्रहार कर
उसी स्वातंत्र्य स्वर्ग में इस सोते हुए भारत को जगाओ!

एक्सप्रेस समूह को उनके प्रतिरोध के लिए आपातकाल में भारी संकट का सामना सरकारी तंत्र के हाथों झेलना पड़ा था। भारतीय प्रेस के साथ-साथ विदेशी अखबारों को भी सरकार ने नहीं बक्शा। 'लंदन टाइम्स', 'न्यूज वीक' और 'लंदन डेली टेलीग्राफ' के संवाददाताओं को तत्काल भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए थे। 'न्यूज वीक' के संवाददाता लॉरेन जेनकिन्स ने भारत निकाला के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखाः

'फ्रेंको के स्पेन से माओ के चीन तक दुनिया को कवर करने के १० वर्षों में, मैंने कभी भी इस प्रकार की कठोर और सम्पूर्ण सेंसरशिप का सामना नहीं किया।'

विश्व भर में इस आपातकाल को लेकर तीव्र प्रतिक्रियाएं बौद्धिक समूह से देखने को मिलती है। विश्व की सरकारों ने लेकिन सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देने से परहेज तब किया था। आपातकाल का प्रभाव लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्र पर अवश्य पड़ा। १९७४ में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को 'वाटरगेट कांड' में फंस जाने पश्चात इस्तीफा देना पड़ा था। उनके स्थान पर राष्ट्रपति बने जेराल्ड फोर्ड ने भारत में आपातकाल घोषित किए जाने पश्चात् अपनी प्रस्तावित भारत यात्र को टाल दिया। एक वर्ष पश्चात् अपनी चीन यात्र से पहले भारत में चल रहे आपातकाल पर टिप्पणी करते हुए दिसंबर १९७५ में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था-

'साठ करोड़ लोग वह गंवा चुके हैं जो उनके पास १९४० के मध्य से था। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वहां लोकतांत्रिक प्रणाली, जैसी अमेरिका में है, वापस लागू हो जाएंगी।'

वाशिंगटन में अप्रवासी भारतीयों ने आपातकाल का विरोध करने के लिए एक संस्था 'इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी' का गठन करा। इस संस्था के बैनर तले भारतीय दूतावास के सामने एक विशाल प्रदर्शन ३० जून को आयोजित किया गया था। अमेरिकी श्रमिक संगठनों ने आपातकाल की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए एक बयान जारी कर कहा-

'भारत एक पुलिस राज्य में बदल गया है जहां लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है।'

ब्रिटेन ने युवराज प्रिंस चार्ल्स की भारत यात्र रद्द कर अपना प्रतिरोध दर्ज कराया था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के प्रतिनिधि मार्क टली को सेंसरशिप न मानने चलते भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पश्चिमी देशों की बनिस्पत पूर्वी देशों, विशेषकर सोवियत संघ व अन्य पूर्वी यूरोपियन देशों से इंदिरा को आपातकाल के दौरान किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं देखने को मिलता है। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र 'प्रावदा' ने खुलकर भारतीय प्रधानमंत्री के निर्णय को सराहते हुए लिखा था-

'दक्षिणपंथी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक है, सेंसरशिप के जरिए प्रेस को सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने से रोका जा सकेगा।'

भारतीय प्रेस को खामोश करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जाने लगे। नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने समाचार पत्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए सरकार के विरोध में लिखे हर समाचार, लेख, कार्टून इत्यादि के प्रकाशन पर पाबंदी लगा डाली थी। जयप्रकाश नारायण की पत्रिका 'एवरीमैन' और 'प्रजानीति', जॉर्ज फर्नांडीस की 'प्रतिपक्ष' और स्वतंत्र पार्टी के नेता पीलू मोदी की पत्रिका 'मार्च ऑफ इंडिया' का प्रकाशन कड़े सेंसरशिप नियमों चलते बंद कर दिया गया। जनसंघ के मुख्य पत्रों 'मदरलैंड' और 'ऑर्गेनाइजर' को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। कई विदेशी समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को आपातकाल लगने के साथ ही भारत छोड़ने के आदेश थमा दिए गए थे। अमेरिकी अखबार 'द वाशिंगटन पोस्ट' के प्रतिनिधि लुइस- एम साइमन्स को सबसे पहले भारत निकाला दिया गया। साइमन्स को यह आदेश उनके एक लेख 'संजय गांधी एंड हिज मदर' के चलते थमाया गया था। इस लेख में उन्होंने संजय और इंदिरा पर कड़े प्रहार करते हुए लिखा था-

'अपने सबसे निकटतम मंत्रिमंडलीय सदस्यों तक को शक की नजरों से देखने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत के सबसे नाजुक दौर में, अपने विवादास्पद पुत्र संजय पर निर्भर रहने लगी हैं... एक पारिवारिक मित्र जो कुछ महीनों पहले संजय एवं इंदिरा के घर रात्रि भोज पर आमंत्रित था, का कहना है कि उसने बेटे (संजय) को मां (इंदिरा) के मुख पर 'छह' बार तमाचे मारते देखा। इस मित्र के अनुसारः 'वह (इंदिरा) चुपचाप तमाचे खाती रहीं। वे संजय से मृत्यु समान डरती हैं।'

क्रमशः

#GetYourSelfPlaced®

First Choice
For the Brightest of Minds

GALGOTIAS UNIVERSITY

offers edge to its students with **Top-Notch Placements, World Class Research Environment & Academic Excellence**

₹1.5 CRORE — OpenZeppelin
₹44 LACS — Microsoft
₹36 LACS — AUTODESK
₹33 LACS — COMMVAULT

Suryansh Pratap B.Tech, CSE Student
Guru Prakash Singh B.Tech, CSE Student
Tanishk Merothiya B.Tech, CSE Student
Sakshi Gaur B.Tech, CSE Student

We are committed to **carry forward the vision** of our Visionary Honourable Prime Minister **Shri Narendra Modi Ji** of **making India a Vishvaguru** and the dream of our Dynamic Honourable Chief Minister of Uttar Pradesh **Shri Yogi AdityaNath Ji** for making the **State of UP a truly Global Knowledge Superpower.**

ADMISSION OPEN 2023-24 for CAREER-FOCUSED UG / PG / Ph.D. DEGREES in

- Computing Science and Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics & Communication Engineering
- Mechanical Engineering
- Civil Engineering
- Design
- Education
- Nursing
- Liberal Education
- Media and Communications Studies
- Law
- Agriculture
- Basic & Applied Science
- Finance & Commerce
- Pharmacy
- Medical & Allied Sciences
- Business
- Hospitality & Tourism
- Polytechnic

GALGOTIAS UNIVERSITY
(Under the Uttar Pradesh Private Universities Act No. 12 of 2019)

For the complete list of programmes offered and to apply online visit:
https://admissions.galgotiasuniversity.edu.in
www.galgotiasuniversity.edu.in

Plot No.2, Sector 17-A, Yamuna Expressway, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh, India.

Call @ 0120-4370000,
+91-97173 00418, +91-95828 47072
+91 99710 26125

Scan to know more

NAAC A+
Accreditation in First Cycle

This makes Galgotias University the **only private university in Uttar Pradesh** with the **highest NAAC score** and the **second highest amongst state private universities in the entire country** with a NAAC score of 3.37 out of 4 awarded by NAAC in the **First Cycle of NAAC Accreditation.**

Strategic Location
Galgotias University is located in the **midst of a Commercial/Industrial hub** & is located minutes away from upcoming **Noida International Airport.** The strategic location will help students gain access to opportunities as new investments to the tune of **35 Lakh Crore are planned, which shall create over 25 Lakh jobs in the Greater Noida region alone.**

Record Breaking Placements
Galgotias University has **broken all previous records** for placements with **800+ recruiters** giving Galgotias students multiple job offers: some of the recruiters are Infosys, Cognizant, Wipro and more.

Research Excellence & Awards
Galgotias University **Ranked Top 5 in India** as per the Indian Patent office Report for Academic Institutes and Universities, **filled 417 patents**

Galgotias University **Ranked in PLATINUM BAND (GRADE A++)** for **Institution of Academic Excellence** OBE Rankings 2022

Grade A++ PLATINUM BAND OBE RANKINGS 2022

Achieves excellence in quality education, & implementation of the latest teaching-learning methodologies, including the outcome-based education models.

The **Highest Benchmark** of **Academic Excellence, Placements & Research** for **Computer Science Engineering, Mechanical Engineering, Electronics & Communications, Engineering, B.Pharm** and **MBA**

NBA NATIONAL BOARD of ACCREDITATION ACCREDITED Tier 1

Students who graduate in the above mentioned NBA accredited programmes during the validity period of accreditation will be deemed to have graduated with an NBA accredited degree.

Galgotias University **Ranked #59 in India** (Pharmacy Category) by NIRF (National Institutional Ranking Framework) 2022

nirf NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK

#93 Management #147 Engineering

TOP RANKED BY INDIA TODAY

Galgotias University **Ranked#1** in India in Academic and Research Excellence as per India Today - **MDRA Best Universities Survey 2022.**

Galgotias University **School of Law Ranked #3** in India in Academic Excellence by **INDIA TODAY-MDRA Survey - July 2022**

Galgotias University has been listed in the Band **"Excellent" for "Innovation & Entrepreneurship Development".** Under University & Deemed to be University (Private / Self Financed) (Technical) in the AIIRA Ranking 2021.

ARIIA

Ranking#2 in Uttar Pradesh Ranking#46 in India

Thank You India! for **your continuous trust** in us, **Yet another milestone in our glorious success story.**

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी National Testing Agency

Galgotias University is amongst **top 8 most preferred universities** in the country as per **CUET (Common University Entrance Test) applications.** Galgotias University **received record breaking 399,373 applications.**

School of Business Galgotias University **Ranked#2 in North India by TOP B-Schools Under Private Universities (Zonewise)**

OPEN

Galgotias University has been awarded **IAR-Placement Audit (5 stars) indicating HIGHEST performance capability in placing its students.**

Infomerics Analytics & Research

Galgotias University, School of Hospitality & Tourism, India is ranked among the **TOP 50 Best Hospitality and Hotel Management Schools** in the World for 2023 as per CEOWORLD, USA

CEOWORLD Magazine

Galgotias University awarded as the star performing institute in internships with an **All India 6th Rank in AICTE - EduSkills virtual internship programme 2022.**

EduSkills® Nation Building Through Skills

National Employability Award 2023 (AMCAT Test) for School of Computing Science and Engineering, Galgotias University on account of students performance being among the top 10% Nationally.

आरीएनीआई नी : UTTHIN/2009/29438, उत्तर प्रदेश : UP/GBDA58/2014-16